▶▶ कृषि ▶▶ विश्लेषण ▶▶ जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

# स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/—रू.

वैशाख–ज्येष्ठ 2080, मई 2023

## मुफ्तखोरी के कारण कर्ज में डूबते राज्य

स्वदेशी गतिविधियां **स्वावलंबी भारत अभियान**

# प्रांतीय कार्यशालाएं व विचार वर्ग

सचित्र झलक

कोकण प्रांत

स्वदेशी गतिविधियां **स्वावलंबी भारत अभियान**

# जिला रोजगार सृजन केंद्र

त्रिपुरा

गंजम जिला, ओड़िशा

भोपाल, मध्य भारत

स्वदेशी पत्रिका

# अनुक्रम

वर्ष–31, अंक–5
वैशाख–ज्येष्ठ 2080 मई 2023

*संपादक*
**अजेय भारती**

*सह–संपादक*
**अनिल तिवारी**

*पृष्ठ सज्जा एवं टंकन*
सुदामा दीक्षित

*कार्यालय*
**धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग**
**रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022**
से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा **4**
समाचार परिक्रमा **36-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

आवरण कथा – 6
**मुफ्तखोरी के कारण कर्ज में डूबते राज्य**
डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 आजकल
**बदनाम हुए तो क्या? मालामाल तो हुए** ..... अनिल तिवारी

10 विश्लेषण
**क्या पीएलआई योजनाएं काम कर रही हैं** ..... केके श्रीवास्तव

12 आर्थिकी
**डालर का विकल्प बन सकता है रूपया?** ..... विक्रम उपाध्याय

14 शिक्षा
**भारतीय उच्च शिक्षा में सुधार की जरूरत** ..... डॉ. जया कक्कड़

16 मजदूर दिवस
**जस की तस है कामगारों की दशा** ..... शिवनंदन लाल

18 कृषि
**बेरोजगारी दूर करने का दमखम है कृषि में** ..... देविन्दर शर्मा

20 योजना
**वन नेशन – वन राशन कार्ड** ..... डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल

22 ऊर्जा
**क्यों बंद हो रहे परमाणु ऊर्जा के संयंत्र?** ..... विनोद जौहरी

24 तकनीकी
**ईएसजी को प्रभावित करता है एआई!** ..... आलोक कुमार सिंह

26 जल प्रबंधन
**कल के लिए जरूरी है बेहतर जल प्रबंधन आज** ..... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

28 मुद्दा
**दो ट्रिलियन निर्यात की बड़ी छलांग** ..... स्वदेशी संवाद

30 बीच–बहस
**वैश्विक स्तर पर भारतीय सबसे अधिक प्रसन्नता प्राप्त करने की ओर अग्रसर** ..... प्रहलाद सबनानी

33 विचार
**सतही होती जा रही है संबंधों की संवेदना** ..... वैदेही

# पाठकनामा

## सीधी नहीं होती कभी कुत्ते की दुम

कुत्तों की वजह से देश में मारपीट और फौजदारी मुकदमा दायर होने की बात अब आम हो गई है। कुत्तों के हमले की खबरें भी आए दिन अखबारों में छपती रहती है। अभी हाल ही में दिल्ली के शोषण क्लब में कुत्तों की समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने बैठक बुलाई थी। इस बैठक में एक भूतपूर्व चीफ सैक्रेटरी ने डॉग बाइट और दूसरी समस्याओं को गंभीरता से उठाया। मीटिंग में सभी वक्ताओं ने कुत्तों की वजह से बढ़ती समस्याओं का जिक्र किया। मजेदार बात यह हुई कि जहां यह बैठक चल रही थी, ठीक उसके बगल में कुत्तों से प्रेम करने वाले लोगों ने एक अलग बैठक शुरू कर दी। मामला तब और गंभीर हो गया जब दोनों पक्ष आपस में भिड़ने को तैयार हो गए। कुत्ता प्रेमी लोगों को आपत्ति थी कि कुत्ते के खौफनाक चेहरे को क्यों सामने किया जा रहा है, इससे लोगों में पशुओं के प्रति क्रूरता बढ़ेगी। वहीं विरोधी गुट आंकड़ों के साथ यह बार–बार कह रहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा दिल्ली में ही कुत्ते लोगों को काटते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कुत्ते देश के हर हिस्से में लोगों को काटते हैं। कुत्ता काटने के बाद लोग रेबिज की सुई लगवाने को बाध्य होते हैं। सोशल मीडिया पर दो छोटे बच्चों को चार–पांच कुत्तों के मिलकर मार डालने का वीडियो वायरल हुआ था।

दिल्ली तथा आसपास की समृद्ध रिहायशी सोसायटियों में कुत्तों को लेकर मारपीट की बात आम है। पाकुर में कुत्ता लेकर जाने की मनाही है, लेकिन कुत्ता पालक लोग अपने कुत्तों को घुमाने अक्सर सार्वजनिक स्थानों पर ही पाए जाते हैं। ज्ञान चतुर्वेदी ने अपने एक व्यंग में लिखा है कि कुत्ता पालना बड़ा कुत्तई का काम है। राजनीति में तो पक्ष विपक्ष हर जगह होता है, कुत्ते को लेकर भी अब लोग आमने–सामने हैं। यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है कि कुत्तों की श्रद्धा नसबंदी में सबसे अधिक सरकारी भ्रष्टाचार होता रहा है। अगर तंत्र सुव्यवस्थित होता और कुत्तों की बढ़ती आबादी पर समय रहते नियंत्रण रखा जाता, तो निश्चित रूप से समस्याएं कुछ कम होती। पशु चिकित्सकों की माने तो कुत्ते के स्वभाव में खतरनाक बदलाव उनके पालने के तरीके से भी आ रहा है। आज शहरों में दो कमरे के फ्लैट में रहने वाले लोग शौकिया कुत्ता तो पाल लेते हैं, लेकिन कुत्ते को जो स्वच्छंदता चाहिए होती है, वह वे नहीं दे पाते और कुत्ता बिगड़ैल और हिंसक हो जाता है। मनुष्यों ने बहुत सारी समस्याओं का हल किया है। आज के दौर में कुत्ता और मनुष्य के बीच चल रहे जंग को भी काबू करने का इंतजाम करना चाहिए ताकि आवारा बिगड़ैल और हिंसक कुत्ते इंसानी जिंदगी पर भारी न पड़े, वही सदियों से मनुष्यों के साथ रहते आए कुत्तों को सामाजिक प्राणी मानते हुए उनका भी भरण पोषण होता रहे।

*डॉ. पराक्रम सिंह धुंधरी,* आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।


**संपादकीय कार्यालय**

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
**swadeshipatrika@rediffmail.com**

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)


# कहा–अनकहा

**स्वास्थ्य के बारे में भारत का दृष्टिकोण केवल बीमारी की कमी पर नहीं रुकता है, हमारा लक्ष्य सभी के लिए शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण और खुशहाली पर केंद्रित है।**

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

**डिग्री के बजाय कौशल और दक्षता भविष्य को आगे बढ़ाएगी। ईश्वर प्रदत्त मानव बुद्धि और कृत्रिम मेधा (एआई) के बीच निरंतर प्रतिस्पर्धा होगी।**

धर्मेन्द्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, भारत

**भारत को उत्पादों में चीनी के अनुपात में कर स्लैब रखते हुए चीनी आधारित कर (एसबीटी) प्रणाली की ओर बढ़ना चाहिए, जिसका अर्थ है, उत्पादों में चीनी जितनी अधिक होगी, कर उतना ही अधिक होगा।**

प्रवीण खांडेलवाल, महासचिव, कैट

**हमें ऐसा कानून बनाना चाहिए, जहां गूगल सहित अन्य तकनीकी दिग्गज अपने एकाधिकार का दुरुपयोग करके छोटे स्टार्ट–अप का शोषण न कर सकें। सीडीसीएल का गठन इस साल फरवरी में सरकार द्वारा डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम की आवश्यकता की जांच करने और मसौदा तैयार करने के लिए किया गया था।**

डॉ. अश्वनी महाजन, राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

## संपादकीय

# प्रौद्योगिकी में लंबी उड़ानः नेशनल क्वांटम मिशन

कई दशक पूर्व कंप्यूटरों का अविष्कार हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर के विकास के साथ–साथ कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में भारी सुधार भी हुआ, जिसके चलते संचार, स्वास्थ्य, ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, अंतरिक्ष आदि में अभूतपूर्व प्रगति हुई। इस प्रगति को आज की भाषा में चौथी औद्योगिक क्रांति भी कहते हैं। लेकिन इस विकास की अपनी सीमाएं रही। यहीं नहीं इसकी सबसे बड़ी समस्या यह रही कि कंप्यूटरों को विभिन्न प्रकार के वायरस और मेलवेयर भेजकर अथवा हैक करके कब्ज़ाया जा सकता है। इससे पूरी व्यवस्था ठप्प हो सकती है। पूर्व में ऐसा हुआ भी है। वित्तीय धोखा धड़ी तो रोज़मर्रा का विषय है। इससे देशों की सुरक्षा पर भी लगातार ख़तरा मंडरा रहा है। क्वांटम प्रौद्योगिकी कंप्यूटर प्रणाली में एक बड़े बदलाव और विकास के रूप में देखी जा रही है, जिससे कंप्यूटरों को पहले से कहीं ज़्यादा तीव्र, प्रभावी और सुरक्षित बनाया जा सकता है।

अप्रैल 19, 2023 को केंद्रीय केबिनेट द्वारा नेशनल क्वांटम मिशन के लिए 6003 करोड़ रूपये की अनुमति के बाद भारत दुनिया में 7वां देश बन गया है, जिसका अपना एक क्वांटम मिशन है। इससे पहले संयुक्त राज्य अमरीका, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा और चीन का ही अपना समर्पित क्वांटम मिशन है। इस विषय की शुरूआत दिसंबर 2018 में हुई थी, जब नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 'नेशनल मिशन ऑन साइबर फिजिकल सिस्टम्स' हेतु 3660 करोड़ रूपये की घोषणा की गई थी। अप्रैल 2023 से प्रारंभ नेशनल क्वांटम मिशन के 4 हिस्से होंगे। पहले तीन हिस्से हैं– क्वांटम कम्प्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन (संचार) एवं क्वांटम सेंसिंग (संवदेन) एवं चौथा हिस्सा उपरोक्त तीनों कार्यक्रमों हेतु उपकरणों का निर्माण है।

माना जा रहा है कि इससे पूर्व क्वांटम मिशन अपनाने वाले देश भी अभी शोध एवं विकास के स्तर पर ही हैं, और इनमें से किसी ने भी क्वांटम तकनीकी का अनुप्रयोग शुरू नहीं किया है। इस प्रकार नेशनल क्वांटम मिशन को अपनाने के कारण भारत भी इन देशों के समकक्ष आ गया है। क्वांटम कंप्यूटर आधुनिक कंप्यूटरों की तुलना में बहुत तीव्र और अद्यतन हैं। कंप्यूटिंग शक्ति में इससे अभूतपूर्व विकास होगा। इनमें जटिल समस्याओं को हल करने की भी क्षमता है जो वर्तमान में हमारी पहुँच से परे हैं। क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण क्वांटम एन्क्रिप्शन तकनीकें पारंपरिक एन्क्रिप्शन विधियों की तुलना में अधिक सुरक्षित होती हैं। क्वांटम संचार नेटवर्क पारंपरिक नेटवर्क की तुलना में द्रुत गति से और अधिक सुरक्षित रूप से सूचना प्रसारित कर सकते हैं, जिनमें पूरी तरह से हैकिंग से मुक्त होते हैं। इसमें सुरक्षित संचार की क्षमता होती है। इसलिए इस मिशन के कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य है – एक लंबी दूरी का संचार।इस मिशन के फलस्वरूप संचार व्यवस्था में अभूतपूर्व क्रांति तो आयेगी ही, भारत विश्व में इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में आ सकता है।

गौरतलब है कि वर्तमान समय की कम्प्यूटर प्रक्रिया दो अंकों 'एक' और 'शून्य' पर आधारित है। लेकिन इस मिशन के अंतर्गत बनाए जा रहे क्वांटम कम्प्यूटरों की प्रक्रिया में 'क्यूबिट्स' अथवा 'क्वांटम बिट्स' इकाईयां रहेंगी। पहले 5 वर्षों में 50 से 100 क्यूबिट्स वाले कम्प्यूटर बनेंगे और 8 वर्षों में 50 से 1000 क्यूबिट्स वाले कम्प्यूटरों का निर्माण शुरू हो जाएगा। इन क्वांटम उपकरणों के निर्माण हेतु साजो–सामान तैयार करने में यह मिशन काम करेगा। इस प्रकार के कम्प्यूटरों के निर्माण से सेटेलाईट आधारित संचार व्यवस्था संचालित होगी और अन्य देशों के साथ सुरक्षित क्वांटम संचार संभव हो पाएगा।

गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से भारत ने डिजिटलाइजेशन में अभूतपूर्व प्रगति की है। जनधन खाते, आधार और मोबाईल की तिगड़ी यानि 'जैम ट्रिनिटी' के कारण न केवल सरकार द्वारा लोक कल्याण सेवाओं की डिलीवरी, बल्कि प्रत्यक्ष नकद राशि का लाभार्थियों को सीधा भुगतान भी संभव हो सका है। उधर जो भुगतान पूर्व में बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से अथवा नकद के लेनदेन से होते थे, वे अब बेहद आसान तरीके से युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से होने लगे हैं। उधर ई–कॉमर्स ने जहां लोगों के लिए जीवन आसान बना दिया है, वहीं उसके रोजगार आदि पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के कारण उससे आशंकाएं भी निर्माण हो रही हैं। इसके समाधान के लिए सरकार ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स के नाम से एक नई व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रही है।

शिक्षा हो, लैंड रिकॉर्ड हो, चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य या बड़े पैमाने पर नागरिकों को सेवा प्रदान करने का कार्य हो, इन सबको आधुनिकतम तरीके की कम्प्यूटर व्यवस्था से ही अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन पिछले समय में कंप्यूटर व्यवस्था में वायरस, मेलवेयर आदि और अपराधिओं और दुश्मन देशों द्वारा हैकिंग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि इन सबसे निपटने के कारगर उपाय करने के बावजूद कई बार निजी व्यक्तियों, कारपोरेट एवं सरकारी संस्थानों, सरकारी विभागों, वायुयान व्यवस्था आदि को उनके भारी नुकसान वहन करने पड़े हैं।

एक ऐसी कम्प्यूटर व्यवस्था जो तीव्र हो, जिसमें बहुआयामी प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जा सके, जो बिग डाटा को समाहित कर सके और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसकी हैकिंग न हो सके, उसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। ऐसे में क्वांटम फिजिक्स में हो रही शोध और नवाचार से भारत अलग नहीं रह सकता। भारत सरकार का राष्ट्रीय क्वांटम मिशन भारत को डिजिटलाईजेशन, शोध एवं विकास, अंतरिक्ष विज्ञान, नागरिक सेवाओं के बेहतर निष्पादन समेत कई मामलों में दुनिया से आगे ले जाएगा। कम्प्यूटर और सॉटवेयर के क्षेत्र में भारत की अभी तक की प्रगति यह इंगित कर रही है कि हम आगे आने वाले कुछ ही वर्षों में इस क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं।

# मुफ्तखोरी के कारण कर्ज में डूबते राज्य

पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने भाषणों में एक बात बार–बार दोहरा रहे हैं कि मुफ्त की रेबड़ियां बांटने की राजनीति इस देश को घुन की तरह खोखला कर रही है। गौरतलब है कि पिछले एक–दो दशकों में विभिन्न राज्यों में राजनीतिक पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए विभिन्न प्रकार की मुफ्त योजनाओं की घोषणा करती रही हैं। मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त महिला यात्रा, सभी किसानों को उनकी भूमि के आधार पर कैश ट्रांसफर, मुफ्त मंगल सूत्र, मुफ्त टेलीविजन, मुफ्त लैपटॉप, स्कूटर समेत कई प्रकार की मुफ्त योजनाएँ राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि कई राजनीतिक दल इससे लाभ उठाते हुए कई राज्यों की सरकारों में काबिज भी हो गए। विभिन्न राज्यों में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त की योजनाओं की एक लंबी सूची बनती जा रही है।

आंध्र प्रदेश के बारे में रिजर्व बैंक का यह भी कहना है कि आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों की राज्य सरकारें बजट में घोषित सार्वजनिक उधारी से इतर कई प्रकार से सरकारी कर्ज ले रही हैं, जो चिंता का विषय है। स्थिति तो यह है कि आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार तो भविष्य के राजस्व को रहन रख ऋण ले रही है। आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त रिजर्व बैंक ने 9 और राज्यों को अगाह किया है कि उनकी उधारी उनकी धारण क्षमता से बहुत अधिक हो चुकी है। इनमें से बिहार, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल को अत्यधिक दबाव में बताया गया है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और केरल में औसतन सरकारी उधारी राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत से ज्यादा है, जिसमें पंजाब में यह 9.6 प्रतिशत है और आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में क्रमशः में यह 6.1 और 6.0 प्रतिशत है। इसके अलावा हरियाणा में यह 5.3 प्रतिशत और केरल में यह 5.1 प्रतिशत है।

*किसी भी राज्य के विकास के लिए जरूरी है कि उसमें निवेश बढ़े। इन्फ्रास्ट्रक्चर के अभाव में निवेश प्रभावित होता है और उसके कारण राज्य का विकास भी। जरूरी है कि राज्यों द्वारा दी जा रही मुफ्त की स्कीमों पर अंकुश लगाकर देश के विकास को गति दी जाए।*

**– डॉ. अश्वनी महाजन**

गौरतलब है कि भारत राज्यों का एक संघ है, इसलिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के ऋण मिलाकर ही संपूर्ण सरकार के ऋण माने जाते हैं। वर्ष 2003 में पारित एफआरबीएम कानून के संदर्भ में बनाई गई एफआरबीएम समिति ने 2017 में यह सुझाव दिया था कि सरकार (केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों) के जीडीपी के अनुपात में ऋण की सीमा 60 प्रतिशत होनी चाहिए, जिसमें केन्द्र सरकर के ऋण की सीमा 40 प्रतिशत और राज्य सरकार के ऋण की सीमा 20 प्रतिशत होनी चाहिए।

वर्ष 2020–21 देश और दुनिया के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। एक ओर सरकारों की आमदनी भारी रूप से घट गई और दूसरी ओर कोरोना महामारी से निपटने हेतु स्वास्थ्य, सामाजिक सेवाओं और खाद्य सहायता पर खर्च अत्यधिक बढ़ गया। स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार की कुल देनदारियां जीडीपी के अनुपात के रूप में 2019–20 में 50.9 प्रतिशत से बढ़ती हुई 2020–21 में 61.01 प्रतिशत तक पहुंच गई। लेकिन इसके बाद यह 2021–22 में ये घटकर 57.33 प्रतिशत, 2022–23 में 55.88 प्रतिशत तक रह गई। इसी प्रकार से राज्य

सरकारों की देनदारियां जीडीपी के अनुपात में वर्ष 2019–20 में 26.66 प्रतिशत, 2020–21 में 31.08 प्रतिशत, 2021–22 में 28.71 प्रतिशत और 2022–23 में 27.87 प्रतिशत रही। यदि आम सरकार (केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों मिलाकर) की कुल देनदारियां 2019–20 में 77.56 प्रतिशत से बढ़ती हुई 2020–21 में 92.09 प्रतिशत तक पहुंच गई। इसके बाद यह घटती हुई 2021–22 में 86.04 प्रतिशत और 2022–23 में 83.75 प्रतिशत तक पहुंच गई।

गौरतलब है कि केन्द्र सरकार का घाटा और देनदारियां दोनों ही अत्यंत पारदर्शी होते हैं और उसके लिए गलत आकलन की आशंका नहीं होती। लेकिन राज्य सरकारों की देनदारियों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाल ही में भारत के अंकेक्षक एवं महालेखाकार (कैग) ने भी राज्यों के बजटीय और राजकोषीय प्रबंधन के बारे में अपनी कुछ टिप्पणियां की हैं। कैग का कहना है कि वर्ष 2020–21 में अधिकांश राज्यों में ऋण जीएसडीपी अनुपात लक्षित 20 प्रतिशत (एफआरबीएम के अनुसार) से ज्यादा है। पंजाब में यह 48.98 प्रतिशत, राजस्थान में 42.37 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 37.39 प्रतिशत, बिहार में 36. 73 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 35.30 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 31.53 प्रतिशत, तेलंगाना में 27.80 प्रतिशत, तमिलनाडु में 27.27 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 26.47 प्रतिशत तक पहुंच गया है। गौरतलब है कि ऋण के कैग के आँकड़े राज्य सरकारों द्वारा दिये गये आँकड़ों से भिन्न हैं। और यदि राज्य के सरकारी उद्यमों और राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को भी शामिल कर लिया जाए तो 2020–21 तक राजस्थान में ऋण जीएसडीपी अनुपात 54.94 प्रतिशत और पंजाब में तो यह 58.21 प्रतिशत तक पहुंच चुका था। आंध्र प्रदेश में भी यह 53.77 प्रतिशत आकलित किया गया है। इसके बाद तेलंगाना में यह 47.89 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में 47.13 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल और बिहार में भी यह क्रमशः 40.35 प्रतिशत और 40.51 प्रतिशत है, और तमिलनाडु में यह 39.94 प्रतिशत।

यदि कैग द्वारा इन राज्य सरकारों की समायोजित देनदारियों की तुलना राज्य सरकारों द्वारा दिए गए आंकड़ों से की जाए तो यह 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक अधिक दिखाई देता है। हालांकि एफआरबीएम एक्ट के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकारों की देनदारियां निर्धारित सीमा से ज्यादा है, लेकिन कैग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार राज्य सरकारों का अपेक्षित सीमा से अंतराल लगातार बढ़ता जा रहा है।

## मुफ्त की रेवड़ियाँ और राज्यों पर बढ़ता कर्ज

आंध्र प्रदेश के बारे में रिजर्व बैंक का कहना है कि पंजाब के बाद आंध्र प्रदेश मुफ्त की योजनाओं पर खर्च करने वाला देश का दूसरा ऐसा राज्य है। गौरतलब है कि पंजाब में कुल कर राजस्व का 45.5 प्रतिशत मुफ्त की योजनाओं पर खर्च होता है और आंध्र प्रदेश में 30.3 प्रतिशत। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो पंजाब में राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.7 प्रतिशत मुफ्त की योजनाओं में खर्च होता है तो आंध्र प्रदेश में 2.1 प्रतिशत। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सब्सिडी पर खर्च कर राजस्व का 28.8 प्रतिशत, झारखंड में यह 26.7 प्रतिशत है।

गौरतलब है कि कैग के आकलन के अनुसार उन राज्यों पर कर्ज ज्यादा है, जहां मुफ्त की स्कीमों पर ज्यादा खर्च किया जा रहा है। इसमें सबसे ऊपर पंजाब और आंध्र प्रदेश है। जहां कुल राजस्व का भारी हिस्सा मुफ्त की योजनाओं पर खर्च होता है। आंध्र प्रदेश के अलावा दक्षिण का एक अन्य प्रांत तमिलनाडु है, जो जरूरत से ज्यादा मुफ्त की योजनाओं पर खर्च करता है। यूं तो दिल्ली भी मुफ्त की स्कीमों में काफी आगे है, लेकिन दिल्ली पर इस कारण से कर्ज इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि राज्य का प्रति व्यक्ति राजस्व शेष भारत से लगभग दुगुना है। लेकिन दिल्ली सरकार द्वारा मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा के कारण दिल्ली की वित्तीय स्थिति अत्यंत खराब हो गई है। आम आदमी पार्टी के सत्ता पर काबिज होने से पहले दिए गए तमाम वायदे जैसे 20 नए कॉलेज, फ्री वायफाई, 20 हजार सार्वजनिक शौचालय, महिला सुरक्षा फोर्स, 5 लाख सीसीटीवी, 8 लाख नौकरियों का सृजन, एक लाख युवकों को कौशल प्रशिक्षण आदि सारे वायदे अब तक हवा हो चुके हैं। दिल्ली की नागरिक सुविधाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। नई सड़कें, फ्लाईओवर, स्कूल और कॉलेज खोलना तो दूर दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं।

जब कोई प्रांत मुफ्त की स्कीमों पर अपने कर राजस्व का इतना बड़ा हिस्सा खर्च कर देता है तो स्वाभाविक रूप से आवश्यक सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसका पूँजीगत खर्च कम हो जाता है। राज्य सरकार पर कर्ज बढ़ता चला जाता है, जिसके चलते भविष्य में भी सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ–साथ यातायात और अन्य आवश्यक सेवाएं भी प्रभावित होती हैं। किसी भी राज्य के विकास के लिए जरूरी है कि उसमें निवेश बढ़े। इन्फ्रास्ट्रक्चर के अभाव में निवेश प्रभावित होता है और उसके कारण राज्य का विकास भी। जरूरी है कि राज्यों द्वारा दी जा रही मुफ्त की स्कीमों पर अंकुश लगाकर देश के विकास को गति दी जाए। ❑❑

# बदनाम हुए तो क्या? मालामाल तो हुए

गो–एयर से गो–फर्स्ट बनी वाडिया ग्रुप की एयरलाइंस कंपनी ने एनसीएलटी के चौखट पर पहुंचकर खुद को दिवालिया घोषित करने की अर्जी दी है। किराए के सिर्फ दो जहाज से कारोबार शुरू करने वाली वाडिया ग्रुप की कंपनी 61 विमानों का जखीरा खड़ा करने के बाद अचानक कारोबार से मुंह मोड़ रही है। दिवालिया घोषित किए जाने के लिए सरकार के समक्ष गिड़गिड़ा रही है। आखिर क्यों? व्यापार में हानि और लाभ दोनों की संभावना हमेशा बनी रहती है लेकिन हर व्यापारी मुनाफा को ही अपना धर्म मानकर व्यापार को आगे बढ़ाता है। ऐसे में बढ़–चढ़कर खुद को दिवालिया घोषित करने की घटनाओं से आम आदमी का कान खड़ा होना स्वाभाविक है। व्यापारियों द्वारा खुद को दिवालिया घोषित करना कहीं उनके लाभ कमाने का रणनीतिक हिस्सा तो नहीं है?

हमारे देश के अधिकांश हिस्सों में आज भी दिवालिया होना सामाजिक शर्म का विषय माना जाता है। जिस किसी व्यापारी का दिवाला निकल जाता है वह लज्जा से मुंह छुपाते फिरता है।पर आजकल जिस तरह से नामी–गिरामी कंपनियां खुद को दिवालिया घोषित कर रही है, उससे यह लगने लगा है कि अब यह शर्म का नहीं बल्कि लाभ का धंधा हो गया है। इस तरह का ट्रेंड वर्ष 2016 में शुरू हुआ जब दिवाला और दिवालिया संहिता नामक नया कानून बना। इस नए कानून ने व्यापारियों को छूट दी कि अगर आप बैंक का कर्ज लौटा नहीं पा रहे हैं तो खुद को दिवालिया घोषित करिए। सरकारी व्यवस्था आपकी कंपनी बेचकर बैंकों और दूसरों के कर्ज लौटा देगी। देश में इससे पहले तक दिवालियापन से जुड़े कम से कम 12 कानून थे जिनमें से कुछ तो 100 साल से भी अधिक पुराने थे। तब मामलों के निपटान में बहुत अधिक समय लगता था।सरकार ने व्यापार को गति देने के लिए नया कानून बनाया,लेकिन इस कानून के बनने के बाद से ही इसकी खामियां उजागर होने लगी। लगातार यह आरोप लगता रहा कि कानून का गलत इस्तेमाल कर फायदा उठाया जा रहा है। सरकार ने इस कानून में कई बार संशोधन भी किया है। कानून की धारा 7, धारा 12 एवं धारा 29 में मुकदमा दायर करने, नीलामी में भाग लेने तथा 180 दिनों के भीतर सारी प्रक्रिया पूरी कर लेने का आश्वासन है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि दो 2 साल से भी अधिक समय से मामले अधिकारियों के समक्ष लटके पड़े हैं।

*सरकार कड़े संशोधनों के साथ आगे आए तथा जानबूझकर खुद को दिवालिया घोषित करने वालों से गहन पड़ताल के बाद मामले को पारदर्शी तरीके से निपटाया जाए।*

**– अनिल तिवारी**

प्राप्त जानकारी के मुताबिक 31 जनवरी 2023 तक एनसीएलटी पीठों के पास 21205 मामले लंबित हैं। इनमें दिवाला एवं शोधन क्षमता कोर्ट के तहत 12963 मामले तथा 8242 अन्य मामले शामिल है। भारतीय दिवाला एवं शोधन क्षमता बोर्ड के द्वारा जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक आईबीसी (इंसॉल्वेंसी व बैंकरप्सी कोड) 2016 की शुरुआत के बाद से 31 दिसंबर 2022 तक कुल 6199 सीआइआरपी ही शुरू हो चुके हैं। सीआरपी का अर्थ कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया होता है। आईडीबीआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर 2022 तक मात्र 611 सीआईआरबी का समाधान हुआ। इनमें वित्तीय लेनदारों के लिए लगभग 2.44 लाख करोड़ रुपए मूल्य की उगाही की गई। इस पूरी प्रक्रिया में कई सारी कंपनियों की नीलामी तो हुई लेकिन इन कंपनियों की नीलामी से बैंकों और दूसरे कर्ज दाताओं को बहुत अधिक प्राप्तियां नहीं हुई। सरकार ने खुद बताया है कि नीलाम हो चुकी कंपनियों में सरकारी बैंकों के लगभग 9 लाख करोड रुपए बतौर कर्ज फंसे थे। यह कंपनियां इतने सस्ते में बिकी हैं कि मुश्किल से ढाई लाख करोड़ ही वापस आए हैं। यानी कि लगभग 6.30 लाख करोड़ रुपए डूब गए। अगर इसे तकनीकी भाषा में कहा जाए तो बैंकों ने अपने खाते से 6.30 लाख करोड़ रुपए का राइट ऑफ कर दिया।

कानून का सहारा लेकर कंपनियां या तो खुद या उनके बैंक उन्हें राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ले जाते हैं। ट्रिब्यूनल ऐसी कंपनियों का केस किसी सीए या ऑडिट कंपनी को हल ढूंढने के लिए सौंप देता है। इन्हें बैंक की भाषा में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी आरपी कहा जाता है। आरपी कंपनियों की परिसंपत्तियों की कीमत निर्धारित करता है और आपसी सहमति के बाद नीलामी की प्रक्रिया शुरू करता है। इस पूरे आयोजन के पीछे अधिक से अधिक रिकवरी करने की मंशा होती है। मामले को अधिकाधिक पारदर्शी बनाने के लिए ही नीलामी की प्रक्रिया रखी गई है। लेकिन इस प्रक्रिया के फलितार्थ चौकानेवाले हैं। उदाहरण के लिए वीडियोकान पर 46 हजार करोड रुपए का कर्ज था, पर यह कंपनी मात्र तीन हजार करोड़ में बिक गई। जेट एयरवेज पर 15000 करोड़ का कर्ज था वह महज दो हजार करोड़ में बिकी। रुचि सोया पर 12000 करोड रुपए का कर्ज था, वह महज 4300 करोड में बिकी। 24000 करोड रुपए की कर्जदार आलोक इंडस्ट्री मात्र 500 करोड़ रुपए में नीलाम हो गई। बरिस्ता कॉफी ग्रुप पर 25000 करोड़ रुपए का कर्ज था वह मात्र 1500 करोड़ में बिक गया। इसी तरह रिलायंस नेवल पर 12000 करोड़ का कर्ज था, यह कंपनी सिर्फ 800 करोड रुपए में नीलाम हो गई। ऐसे अनेक मामले हैं।

कानून लाने के पीछे यह धारणा थी की पुराने दिवालिया कानूनों के कारण मामलों को निपटाने में देरी होती है, जिसका असर बैंकों पर पड़ता है। बैंकों को अपना पैसा वसूलने में काफी समय बर्बाद करना पड़ता है वही नए कर्ज बांटने की क्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बैंक भी अक्सर रिकवरी के लिए मजबूत कानून की मांग करते रहे हैं। सरकार ने कानून में समय–समय पर संशोधन भी किया है लेकिन 'तू डाल डाल –मैं पात पात' की कहानी चरितार्थ करते हुए कंपनी मालिक बैंकों का कर्ज चुपके–चुपके अपनी सेल कंपनियों के जरिए या गुप्त और बेनामी खातों के जरिए विदेशों तक भेजते रहे हैं। इसके प्रमाण भी समय–समय पर जांच एजेंसियों को मिलता रहा है। मालूम हो कि आलोक इंडस्ट्री के मालिकों के गुप्त खाता होने की बात पंडोरा पेपर में भी आई थी पर आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बरिस्ता कॉफी के मालिकों ने 127 फर्जी कंपनियों में अपनी 80 प्रतिशत संपत्ति और बैंकों के पैसे चुपके से डाल दिए और खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। गौरतलब है कि देश का आम आदमी वाजिब जरूरत के लिए किसी बैंक से लोन लेता है और चुकाने में थोड़ी चूक हो जाती है तो यही बैंक उसका जीना मुहाल कर देते हैं।

जानकार बताते हैं कि बड़ा कर्ज लेने वाली कंपनियां थोड़ा और बड़ा बनने के चक्कर में खुद को दिवालिया घोषित करती हैं तथा अपनी ही परिसंपत्तियों को अपने किसी गुप्त व्यक्ति द्वारा नीलामी के दौरान खुद हासिल करने की कोशिश करती हैं। ज्ञात हो कि गुजरात और राजस्थान में व्यापारियों का दिवाला होना रसूख की बात मानी जाती है। कहा जाता है कि जिस व्यापारी का जितना अधिक बार दीवाला निकला होता है, व्यापार की दुनिया में उसकी साख और अधिक कीमती होती जाती है।

लेकिन यहां लाख टके का सवाल यह है कि कानून की आड़ लेकर कंपनियों की ओने पौने दाम पर नीलामी कर बैंकों द्वारा उनके कर्ज का बड़ा हिस्सा राइट ऑफ कर दिया जा रहा है।बैंक जो रुपया छोड़ दे रहे हैं दरअसल वह रूपया देश के आम आदमी का है, देश के आयकर दाताओं का है। जाहिर है इसका खामियाजा देर सबेर आम आदमी को ही भुगतना पड़ता है। इसे हम यस बैंक के मामले से आसानी से समझ सकते हैं। लगभग दिवालिया हो चुके यस बैंक को बचाने के लिए स्टेट बैंक ने 15000 करोड रुपए की पूंजी डाली, लेकिन स्टेट बैंक ने अगले ही दिन आम जमा कर्ता का ब्याज दर घटा दिया। ऐसे में जरूरी है कि सरकार कड़े संशोधनों के साथ आगे आए तथा जानबूझकर खुद को दिवालिया घोषित करने वालों से गहन पड़ताल के बाद मामले को पारदर्शी तरीके से निपटाया जाए। ❑❑

# क्या पीएलआई योजनाएं काम कर रही हैं

कोविड महामारी के विश्वव्यापी प्रकोप ने इंसानी विवशताओ को उजागर करने के साथ ही जाहिर कर दिया कि तमाम देशों को आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए जोरदार प्रयासों की दरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आत्मनिर्भर अभियान के लिए देशवासियों को तैयार किया ताकि हालात जटिलता की गिरफ्त में ना आए। केंद्र की सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की। आपूर्ति श्रृंखला की खामियों को उजागर करते हुए उत्पादकता को प्रोत्साहन देने के लिए पीएलआई योजना की शुरुआत की। भारत के प्रधानमंत्री ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात के बोझ को कम करने के लिए पीएलआई के जरिए भारतीय कंपनियों को उत्पादों की बिक्री के आधार पर प्रोत्साहन देने का निर्णय किया था। सरकार विकास दर को बढ़ाने के साथ–साथ रोजगार सृजन में बढ़त, निर्यात में वृद्धि तथा आयात को कम करने के लिए प्रतिबद्ध थी। निश्चित रूप से घरेलू विनिर्माण के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करने में यह आवश्यक कदम था। उम्मीद थी कि सकल घरेलू उत्पादों में विनिर्माण का हिस्सा 16 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो जाएगा। वर्तमान में सेवा क्षेत्र में यह मुकाम हासिल है। अगर विनिर्माण के क्षेत्र में भी बढ़त मिलेगी तो अर्थव्यवस्था में अंतरक्षेत्रीय संतुलन आएगा। लेकिन परिणाम बहुत उत्साहजनक नहीं रहे।

आत्मनिर्भर भारत के लिए जो नीतिगत घोषणा हुई उसमें मूल रूप से ऐसे विनिर्माण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना मूल उद्देश्य रहा है जो लागत, गुणवत्ता, विश्वसनीयता और अन्य मापदंडों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी और उन्नत हो। आशा की गई कि हमारी अर्थव्यवस्था विदेशी पूंजी को भी आकर्षित करेंगी। देश की जनता भी बदलाव के इस अभियान में आगे आए। आत्मनिर्भर भारत के तहत बड़े पैमाने पर गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन सुनिश्चित करने, घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने, उत्पादित वस्तुओं के के निर्यात को बढ़ावा देने के साथ–साथ विनिर्माण क्षेत्र में मेक इन इंडिया के जरिए रोजगार सृजन को मुख्य माना गया। इसके लिए साथ ही कौशल विकास योजना

*पीएलआई योजना ने केवल एक सीमित सीमा तक ही वित्तीय प्रोत्साहन दिया है, अधिकांश मामलों में लाभार्थी देने में विफल रहा है।*
**– के.के. श्रीवास्तव**

शुरु की गई। रक्षा उत्पादन में इस नीति को बढ़ावा दिया गया। विनिर्माण में एफडीआई कि सीमा 49 प्रतिशत से बढ़कर 74 प्रतिशत कर दी गई।

पूरी दुनिया चीन प्लस वन की रणनीति के बारे में विचार कर रही थी कि उसी समय भारत की मेक इन इंडिया पहल निश्चित रुप से सबको आकर्षित करने वाली थी। आत्मनिर्भरता के लिए दुनिया के तमाम देशों में इस तरह की पहल हुई। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर विश्व दृष्टि की गुलाबी तस्वीर उभर कर आई। लेकिन मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की नीति बहुत सार्थक नहीं रही। अतीत के अनुभव बताते हैं कि बिना दृढ़इच्छा शक्ति के प्रोत्साहन राशि देना एक जुआ की तरह ही होता है। भारत में भी आर्थिक टिप्पणीकारों ने आरोप लगाया कि उत्पादन प्रोत्साहन योजना जिस तरह डिजाइन की गई है, जिस तरह से इसे कार्यांवित किया जा रहा है, दरअसल यह एक शार्टकट है। इसमें मजबूत और व्यापक नीतिगत ढांचे का ठोस विकल्प नहीं हैं। इस क्रम में हम कह सकते हैं कि पीएलआई योजना आमतौर पर जटिल होती गई है। इसके दुरुपयोग से बचने के लिए कुशल और प्रभावी प्रशासन की आवश्यकता होती है। इसकी सफलता निर्यात में वृद्धि, गुणवत्ता में वृद्धि और रोजगार उत्पन्न करने की उच्च क्षमता से मापी जा सकती है। टिकाऊ प्रतिस्पर्धी बनने की दिशा में यह लक्ष्य महत्वपूर्ण है। यह रणनीति शिशु उद्योग आर्गुमेंट के समान है जहा सरकार घरेलू उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करती है।

वैश्विक बाजार में फर्म के प्रतिस्पर्धी और उच्च गुणवत्ता वाले उदार व्यापार ढांचे की आवश्यकता होती है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और न ही वर्तमान व्यवस्था के आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में इसकी

**सत्तारूढ़ सरकारों द्वारा 90 के दशक के आर्थिक सुधार चरण के बाद दी गई सब्सिडी से भारतीय विनिर्माण को कोई खास मदद नहीं मिली। अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान नहीं बढ़ा।**

संभावना दिख रही हैं। उदाहरण के लिए सबसे अधिक दबाव वाला मुद्दा सूर्यास्त चरण तक पहुंचने के लिए निशिचत समय सीमा के बारे में है जो कि अब भी अस्पष्ट है। दूसरा यह रिकॉर्डेड तथ्य है कि कुछ क्षेत्रों में पीएलआई के बावजूद आयातित वस्तुएं उपयोगकर्ता के लिए सस्ती रहती हैं। तीसरा पीएलआई संरचना पूंजी गहन विकास की पक्षधर है जिसमें श्रम रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की संभावना नहीं है, बल्कि इससे बेरोजगारी का संकट और बढ़ सकता है। चौथा कुछ उद्योग उच्च केपैक्स आवश्यकताओं की शिकायत करते हैं। कुछ अन्य लोग भूमि अधिग्रहण में देरी पर भी सवाल उठाते हैं। पांचवा इसकी गैर संघीय प्रवृत्ति के कारण दिया गया प्रोत्साहन सामान्य की तरह सामने आता है। घरेलू आर्थिक व्यवस्था की संरचना को मजबूत करने की खातिर प्रदान की गई वित्तीय सहायता की वापसी मुश्किल हो जाती है। छठवां, पहले पीएलआई योजना के तहत सरकार द्वारा दिए गए लाभों को बड़े उद्योगपति कब्जा कर लेते हैं। छोटों के हाथ प्रोत्साहन की सिर्फ मूंगफली ही आती है।

तथ्य यह है कि सत्तारूढ़ सरकारों द्वारा 90 के दशक के आर्थिक सुधार चरण के बाद दी गई सब्सिडी से भारतीय विनिर्माण को कोई खास मदद नहीं मिली। अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान नहीं बढ़ा। यह 16 प्रतिशत के आंकड़े पर स्थिर रहा है। विनिर्माण क्षेत्र कुल रोजगार का 10 प्रतिशत से भी कम का योगदान देता है।

यहां आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का सुझाव उल्लेखनीय है कि भारत को दुनिया का कारखाना बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह केवल इच्छाधारी सोच है, जहां ठोस सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र और अन्य देशों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा है। जरूरी नहीं कि रघुराम राजन की सोच से सब लोग सहमत हो, लेकिन तथ्य है कि पीएलआई योजना में शामिल मेक इन इंडिया अबतक मात्र एक नारा ही साबित हुआ है, क्योंकि भारत का तंत्र कमजोर है और इसकी महत्वकांक्षा को वास्तविकता में बदलने के लिए समर्थन प्रणाली भी अलग है।

निराशाजनक तथ्य यह भी है कि वैश्विक आकार के हिसाब से हम सभी मोर्चों पर अभी प्रतिस्पर्धात्मक नहीं हो सकते, इसलिए विश्व बाजार में बेचने में कमोबेश विफल ही है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि पीएलआई योजना ने केवल एक सीमित सीमा तक ही वित्तीय प्रोत्साहन दिया है, अधिकांश मामलों में लाभार्थी देने में विफल रहा है। ❑❑

# डालर का विकल्प बन सकता है रूपया?

क्या भारतीय रुपया एक वैश्विक मुद्रा बनने जा रहा है? क्या रुपया डॉलर का विकल्प हो सकता है? ये कुछ सवाल इसलिए कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में अमेरिकी डॉलर में कारोबार की बजाय बहुत सारे देश अब किसी और मुद्रा के विकल्प की तलाश में लगे हैं। चूंकि भारत का विदेशी व्यापार उन देशों से ज्यादा है, जिन पर या तो अमेरिका ने आर्थिक पाबंदियां लगा रखी है या जो अमेरिका के साथ किसी न किसी मुद्दे पर टकराव रखते हैं। इसलिए हमारे लिए रुपये को एक ग्लोबल पहचान दिलाना सरल हो सकता है।

हालांकि इस समय कोई भी मुद्रा वैश्विक मुद्रा के रूप में स्थापित नहीं है, फिर भी अमेरिकी डॉलर को यह मान लिया गया है कि यही विश्व व्यापार में सर्वमान्य मुद्रा है। किसी भी देश की आर्थिक मजबूती का आधार ही इस समय उसके डॉलर रिजर्व को माना जाता है। एक समय था कि जब सोना के भंडारण के बराबर किसी देश की मुद्रा की कीमत आंकी जाती थी। यानी कोई देश कितनी मुद्रा का प्रचलन कर सकता था, यह उसके सोना भंडारण और उसकी कीमत के आधार पर तय होता था। पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका आर्थिक रूप से इतना संपन्न और एक स्थिर अर्थव्यवस्था बन गया कि अब अमेरिकी डॉलर के रिजर्व को देश की संपत्ति का आधार माना जाता है। आज विश्व का 60 प्रतिशत से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी डॉलर में है। डॉलर के बाद यूरोपियन मुद्रा यूरो है, जो कुल विदेशी मुद्रा भंडारण में 20 फीसदी हिस्सा रखता है। विश्व स्तर पर भारतीय रुपये की लोकप्रियता चौथे नंबर पर है। पर विश्व की दस मजबूत मुद्रा में हम अभी नहीं आते।

यदि व्यापारिक चलन में किसी मुद्रा की हैसियत सबसे अधिक है तो वह निःसंदेह अमेरिकी डॉलर की है। 85 प्रतिशत वैश्विक लेन देन में डॉलर ही प्रयोग में लाया जाता है। यानी आयात–निर्यात के लिए मान्य वैश्विक मुद्रा डॉलर है। येन और यूरो में भी वैश्विक व्यापार हो रहा है पर डॉलर के मुकाबले बहुत कम। चीन ने बहुत कोशिश की कि युआन को वह वैश्विक मुद्रा के रूप में पहचान दिलाए पर उसके रास्ते में कई बाधाएं हैं, जिसमें अमेरिका और यूरोप के साथ उसके व्यापारिक टकराव भी हैं। कुछ समय पहले युआन को

*नरेंद्र मोदी की सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वर्ष 2047 तक भारत का विश्व व्यापार में हिस्सा 10 फीसदी करने का लक्ष्य रखा है। यदि यह संभव हुआ तो यह भी संभव होगा कि दुनिया हमसे हमारी मुद्रा में व्यापार करने को तैयार हो और रुपये को रिजर्व मनी के रूप में भी रखना शुरू कर दे।*

**–विक्रम उपाध्याय**

वैश्विक मुद्रा बनाने के लिए चीन ने आक्रामक नीति अपनाई थी, लेकिन 2020 के बाद से चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट और अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने डॉलर से प्रतिद्वंद्वता के बजाए युआन को डॉलर के मुकाबले स्थिर रखने में ही सारा ध्यान लगा दिया है। पिछले दो साल में युआन का डॉलर के मुकाबले लगभग 8 फीसदी अवमूल्यन हो चुका है। इस समय लगभग दो फीसदी वैश्विक व्यापार में ही युआन के जरिए लेन देन हो रहा है।

लेकिन यहां बात रुपये की है। भारतीय रूपया कभी भी वैश्विक मुद्रा के रूप में चलन में नहीं आया, हां विगत कुछ वर्षों से कुछ द्विपक्षीय और कुछ बहु पक्षीय व्यापारिक लेन देन में रुपये का महत्व तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2007 में जहां रुपये में वैश्विक व्यापार का प्रतिशत केवल 0.7 था, अब वह बढ़कर 1.6 प्रतिशत हो गया है। लेकिन अब इसमें कुछ तेजी आने की संभावना है। भारत के साथ रुपये में व्यापार करने के लिए 18 देशों के साथ रिजर्व बैंक ने समझौता कर लिया है। इनमें बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजरायल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस, सेसेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, यूगांडा और ब्रिटेन शामिल हैं।

इसका सीधा सा अर्थ है कि इन देशों से आयात का भुगतान हम रुपये में कर सकते हैं और निर्यात के बदले रुपये में भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी देशों में रिजर्व बैंक स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट खोलने की मंजूरी देगा। यह एक अतिरिक्त व्यवस्था है जिसके तहत विदेशों के बैंक भारतीय रुपये वाले खाते रखेंगे और मुद्रा के परिवर्तन की सुविधा प्रदान करेंगे।

रुपये को वैश्विक व्यापार की मुद्रा बनाने के पीछे भारत सरकार की एक लंबी सोच व योजना है। पहला लक्ष्य है कि डॉलर के भंडारण पर आने वाले

**रुपये में वैश्विक व्यापार करने के कुछ फायदे तो कुछ जोखिम भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने की है।**

व्यय को कम करना। विदेशी मुद्रा के रुप में डॉलर हमारे यहां दो खातों में आते हैं। एक निवेश के खाते में और दूसरे ऋण खाते में। ऋण खाते में आई विदेशी मुद्रा का ब्याज भार हर साल सरकार को चुकाना पड़ता है और इसके लिए फिर से विदेशी कर्ज भी लेना पड़ता है। रुपये में विदेशी कारोबार का आकार यदि बढ़ता है तो भारत को विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा।

डॉलर जमा करने का दबाव कम होगा तो रुपये की स्थिरता बनाए रखने का खर्च भी कम होगा। वर्ष 2022 में रुपये को डॉलर के मुकाबले गिरने से बचाए रखने के लिए रिजर्व बैंक ने 82. 8 बिलियन डॉलर अतिरिक्त खर्च किए थे। रुपये में विदेशी कारोबार बढ़ा तो भारत का भुगतान संतुलन घाटा भी कम होगा। भुगतान संतुलन का मतलब है आयात और निर्यात के कुल मूल्य में अंतर। इस समय भारत का व्यापार संतुलन घाटा जीडीपी का 2.6 प्रतिशत है। रुपये में विदेशी कारोबार का एक सीधा फायदा मुद्रा परिवर्तन में आने वाले खर्च में कमी होगा। अभी हमारे आयातक बाहर से सामान मंगाने के लिए रुपये को पहले डॉलर में परिवर्तित कराते हैं, फिर भुगतान करते हैं।

रुपये में वैश्विक व्यापार करने के कुछ फायदे तो कुछ जोखिम भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने की है। अभी सिर्फ करेंट अकाउंट पर ही रुपये को परिवर्तनीय बनाने की मंजूरी है। चूंकि विश्व में भारत की मुद्रा बहुत मजबूत नहीं मानी जाती, इसलिए आशंका रहेगी कि रुपये को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने पर इसकी दर में अनावश्यक गिरावट आ सकती है। बाजार के मैन्यूप्लेटर भारतीय मुद्रा को कभी भी दबाव में ला सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती यह होगी वैश्विक व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की। इस समय भारत का वैश्विक व्यापार में हिस्सा 2 फीसदी से भी कम है और इस स्तर पर हम वैश्विक व्यापार को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। इसलिए रुपये को वैश्विक मुद्रा के तौर पर इस्तेमाल करने की गुंजाइश फिलहाल बहुत नहीं है। हां द्विपक्षीय व्यापारों में हम रुपये का उपयोग लेन देन के लिए कर रहे हैं और इसके बढ़ते जाने की संभावना है।

नरेंद्र मोदी की सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वर्ष 2047 तक भारत का विश्व व्यापार में हिस्सा 10 फीसदी करने का लक्ष्य रखा है। यदि यह संभव हुआ तो यह भी संभव होगा कि दुनिया हमसे हमारी मुद्रा में व्यापार करने को तैयार हो और रुपये को रिजर्व मनी के रूप में भी रखना शुरू कर दे। लेकिन तब तक निर्यात बढ़ाने पर ही जोर देना होगा, ताकि आयात हेतु डॉलर की जरूरत कम हो सके। ❑❑

# भारतीय उच्च शिक्षा में सुधार की जरूरत

आबादी के मामले में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। बीते अप्रैल महीने में भारत की आबादी 142 करोड़ों का आंकड़ा पार कर गई। दुनिया की कामकाजी आबादी का छठवां हिस्सा अकेले भारत से है। दुनिया में 25 साल से कम उम्र के 20प्रतिशत लोग भारत में हैं।यह बड़ी आबादी एक ही समय में भारत के लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है।स्किल इंडिया रिपोर्ट 2022 बताती है कि भारत में शिक्षित युवाओं में से केवल 48प्रतिशत ही रोजगार योग्य है। हमारे देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में जिस बड़ी संख्या में छात्र पास आउट कर बाहर निकलते हैं उसकी तुलना में रोजगार का अवसर बहुत ही कम है। डिग्रियां तो बेतहाशा बढ़ रही है लेकिन रोजगार अनुपात नहीं बढ़ता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि हमारे देश की उच्च शिक्षा आवश्यक रूप से कौशल प्रतिभा को विकसित नहीं कर पाती। पढ़े–लिखे युवाओं में कौशल ना होने के कारण न केवल सामाजिक, भावनात्मक और राजनीतिक कीमत चुकाने की बात आती है बल्कि भारी पैमाने पर आर्थिक कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। भारत का डिजिटल स्किल गैप जीडीपी वृद्धि में सबसे बड़ी बाधा लाता है। अनुमान है कि हर साल 23 प्रतिशत अंक की गिरावट का जोखिम बना हुआ है। पढ़े–लिखे युवक अगर रोजगार प्राप्त नहीं करेंगे तो देश को कोई आर्थिक लाभांश नहीं प्राप्त होगा। वहीं दूसरी तरफ वे नौजवान नकारात्मक दिशा की ओर भी भटक सकते हैं। बेरोजगारी की समस्या हमें सामाजिक अशांति की ओर भी ले जाती है। आज देश में युवकों के स्वयंभू सतर्कता समूहों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे समूह समाज में व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए अधिक जिम्मेदार होते हैं। आज देश में शिक्षा की खराब स्थिति और उसी तरह निराशाजनक स्वास्थ्य देखभाल और पोषण संबंधी नकारात्मक मामले को देखते हुए यही लगता है कि हमारे कर्ताधर्ता कल के कार्यबल में पर्याप्त निवेश नहीं करना चाहते हैं। जब तक देश के नौजवानों को शिक्षित प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा हम आजादी का 75वां साल भले मना ले लेकिन अमृत काल नहीं आएगा।

*शिक्षा संस्थानों का पर्याप्त प्रसार हो और एक समर्थकारी परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जाए ताकि भविष्य के कार्यबल को अस्पष्ट नजरिए के साथ शिक्षित और प्रशिक्षित किया जा सके।*

**– डॉ. जया कक्कड़**

भारत निश्चित रूप से एक युवा देश है जहां के 142 करोड़ लोगों में से लगभग 63 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की हैं। अमृत काल के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए युवाओं को अपना योगदान देना होगा। लेकिन युवा योगदान देने के लायक कैसे बनेंगे, यह बात हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों को गंभीरता से सोचने की जरूरत

है। संख्या–बल का मतलब निश्चित रूप से गुणवत्ता से नहीं है। भारत में उच्च शिक्षा का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है।देश में लगभग 1000 से अधिक विश्वविद्यालय और 41000 से अधिक कॉलेज है। लेकिन इनमें से अधिकतर विश्वविद्यालय और कॉलेज मापदंडों पर बहुत खराब प्रदर्शन करते हैं।

उच्च शिक्षा और शोध किसी राष्ट्र के विकास और प्रगति की रीढ़ होते हैं। यह अनायास नहीं है कि दुनिया के सभी विकसित राष्ट्रों में उच्च शिक्षा को लेकर सरकारी और नियामक संस्थाएं अत्यंत सजग हैं। दुर्भाग्य से भारत में उच्च शिक्षा की नियामक एजेंसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विभिन्न सरकारों का रवैया उच्च शिक्षा को लेकर बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है। वास्तव में भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली की वर्तमान स्थिति जटिल और चुनौतीपूर्ण है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा का विस्तार व्यापक स्तर पर हुआ है, लेकिन क्या यह हमारे देश की उच्च शिक्षा छात्रों को जीवन दृष्टि देने में या उनकी भौतिक मानसिक आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल हुई है। हमारी शिक्षा व्यवस्था की चतुर्दिक समस्याओं में से उच्च शिक्षा की समस्या की तह में जाना ज्यादा जरूरी है। शिक्षा किसी देश के आर्थिक विकास की आधारशिला होती है।

देश में विद्यालय में पढ़ाई करने वाले 9 छात्रों में से एक छात्र ही कॉलेज पहुंच पाता है। उच्च शिक्षा हेतु पंजीकरण कराने वालों का अनुपात हमारे यहां दुनिया में सबसे कम 11 प्रतिशत है जबकि अमेरिका में यह 83 प्रतिशत है। संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की शिक्षा व्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आती है लेकिन जहां तक गुणवत्ता की बात है तो दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग काफी नीचे है। देश के कई विश्वविद्यालयों में पिछले 30 सालों से पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुराना पाठ्यक्रम और जमीनी हकीकत से दूर शिक्षक उच्च शिक्षा को मारने के लिए काफी है। आज शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का जितना खर्च होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में शोध पर 0.8 प्रतिशत खर्च हो रहा है। इसीलिए संख्यात्मक विकास के साथ गुणात्मक विकास वैसा कदमताल नहीं कर पाया है। कुछ विश्वविद्यालयों या कुछ नामी–गिरामी कालेजों को छोड़ दे तो गुणवत्ता के धरातल पर स्थिति निराशाजनक है। दुनिया के नक्शे में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान एक तरह से गायब है। शिक्षण संस्थानों की कमी की वजह से अच्छे कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए कट ऑफ प्रतिशत असामान्य हद तक बढ़ जाता है। संपूर्ण देश में छात्र शिक्षक अनुपात इतना असंतुलित है कि सोच कर ही भयावह लगता है। आईआईटी जैसे संस्थानों मे भी शिक्षकों की कमी है। क्षमताओं से कई गुना विद्यार्थी भर लिए लेकिन उनके लिए पठन–पाठन के जरूरी इंतजाम नहीं कर पाए। देश में सुधार हेतु कोठारी आयोग का गठन हुआ। रिपोर्ट भी आई लेकिन सब ठंडे बस्ते में रख दी गई। 1986 में नई शिक्षा नीति आई थी, इसी तरह 2020 में एक बार फिर नई शिक्षा नीति आई है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बदलते दौर में कोचिंग संस्थान पाठ्य पुस्तकों की बढ़ती कीमत डीम्ड विश्वविद्यालयों की बाढ़ और छात्रों में सिर्फ सरकारी नौकरी पाने की एक आम अवधारणा हमारी उच्च शिक्षा की चुनौतियों को और अधिक बढ़ा रहा है। उच्च शिक्षा की सर्व प्रमुख चुनौती है सभी प्रदेशों में एक समान शिक्षा नीति का ना होना भी है, हालांकि शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया और राज्यों पर कोई भी पाठ्यक्रम केंद्र द्वारा थोपा नहीं जा सकता लेकिन व्यवहार में देखा जाता है कि विश्वविद्यालयों में वही होता है जो यूजीसी अपने यहां बैठ करके तय करती है। हमारे उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्य सामग्री की कमी है आजादी के 75 वर्ष बीत जाने पर भी हमारी उच्च शिक्षा अभी भी मैकाले सिंड्रोम से ग्रस्त है।

हमारे शिक्षण संस्थानों में दूरदर्शिता गतिशीलता और प्रगतिशील नेतृत्व की कमी है। आज शिक्षण संस्थानों में स्वायत्तता पूर्वक नियुक्तियां भी नहीं की जा सकती। अधिकांश नियुक्तियां राजनीतिक निष्ठा को ध्यान में रखकर की जाती है। दिल्ली विश्वविद्यालय में हाल में हुई नियुक्तियां इन गड़बड़ियों की गवाह है। दूसरा नई शिक्षा नीति 2020 में बहुविषयक शिक्षा की कल्पना की गई है।लेकिन विडंबना यह है कि कॉलेज तो दूर की बात विश्वविद्यालयों को भी अपना पाठ्यक्रम निर्धारित करने की स्वतंत्रता नहीं है। तीसरा यह कि आर्थिक बाधाओं के कारण सभी की पहुंच उच्च शिक्षा तक नहीं है। आज निजी तौर पर वित्त पोषित संस्थानों की मौजूदगी बढ़ रही है। बेशक डिजिटल और ऑनलाइन सुविधाओं का प्रसार बीच का रास्ता बनता दिख रहा है लेकिन सरकार ने शिक्षा पर निवेश का वांछित लक्ष्य अब तक हासिल नहीं किया है। और चौथा जो सबसे जरूरी है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में शिक्षण और अनुसंधान को अलग कर दिया गया। जाहिर है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र के लिए समस्याओं के समाधान हेतु आधुनिक शोध ही एकमात्र रास्ता है फिर भी संकाय के सदस्यों द्वारा उत्कृष्ट शोध की सराहना नहीं की जाती। ऐसे में जरूरी है कि शिक्षा संस्थानों का पर्याप्त प्रसार हो और एक समर्थकारी परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जाए ताकि भविष्य के कार्यबल को अस्पष्ट नजरिए के साथ शिक्षित और प्रशिक्षित किया जा सके।❑❑

## मई दिवस/मजदूर दिवस

# जस की तस है कामगारों की दशा

**सन् 1886** में मजदूरों ने पहली दफा शिकागो शहर में रैली निकाली थी तो उनकी एक ही मांग थी कि हमारे काम के घंटे आठ होने चाहिए। तब पुलिस ने उनके ऊपर गोलियां चलाई, जिससे कई मजदूर शहीद हुए। अंततः उनकी बात मान ली गई। काम के घंटे आठ किए गए। उसी की याद में हम 'मई दिवस' मनाते रहे हैं। बीते 137 सालों में दुनिया के साथ भारत में भी संगठित क्षेत्र के मजदूरों की सेवा शर्तों में काफी हद तक सुधार हुआ है, इससे मजदूरों की दशा–दिशा बदली है, बावजूद देश में मजदूरों के बड़े क्षेत्र असंगठित वर्ग के कामगारों की स्थिति निरंतर और अधिक बदतर और श्रम–साध्य होती गई है। सुधार की अनेक घोषणाओं के बावजूद असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को प्रतिदिन 12 से लेकर 16 घंटे तक काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। करोना कॉल के बाद इस तरह के व्यवहार में और वृद्धि हुई है।

हाल के वर्षों में देश की संसद ने तीन प्रमुख प्रमुख श्रम सुधार विधेयक इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, आक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 और कोड आन सोशल सिक्योरिटी 2020 पारित कर कानून बनाया। कोविड–19 की चुनौतियों और भारत के लिए वैश्विक उद्योग कारोबार के बढ़ते मौकों को ध्यान में रखते हुए नए श्रम कानून को नियोक्ता, कर्मचारी तथा सरकार तीनों के लिए फायदेमंद माना गया। कहा गया कि इन कानूनों से श्रमिकों को बहुत सहूलियतें प्राप्त होंगी। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए अलग से फंड तैयार किया जाएगा। खतरनाक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को अनिवार्य रूप से कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधा दी जाएगी। सेल्फ एसेसमेंट के आधार पर श्रमिक अपना पंजीयन करा सकेंगे। घर से काम पर आने जाने के दौरान दुर्घटना होने पर कर्मचारी हर्जाना पाने का हकदार होगा। महिला श्रमिक अपनी इच्छा से रात की पाली में भी काम कर सकेंगे। सभी कामगारों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा तथा इनका हिसाब किताब रखने के लिए अलग से एक लेबर ब्यूरो बनाया जाएगा। उद्यमियों के लिए भी कई फायदे गिनाए गए। मसलन इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने के साथ–साथ श्रम संहिताओं के तहत नियमों का अनुपालन नहीं करने को लेकर अधिकतम सजा सात साल को घटाकर तीन साल कर दिया गया।विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा कारखाने का लाइसेंस लेने की शर्तों में भी ढील दी गई। कारखाना अधिनियम 1948 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधिकांश प्रावधान लागू किए जाने में अत्यधिक रियायतें दी गई। उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यों ने उत्पादन इकाइयों में काम के घंटों को 8 से बढ़ाकर 12 कर दिया।

*मजदूरों के लिए लोकतंत्र का राज और आजादी का अमृत महोत्सव होने का कोई मतलब नहीं है। वह आज भी उतने ही शोषित हैं जितना पहले के दौर में थे। आजादी के अमृत काल के दौरान केंद्र की सरकार द्वारा 80 करोड़ को लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराना इस बात की तस्दीक करता है।*

**– शिवनंदन लाल**

यानि मजदूर जहां से चले थे, कमोबेश फिर से वही आकर के खड़े हो गए हैं। शिकागो में जो सफलता मिली थी वह 137 साल के अंतराल पर फिर अपने पुराने मुकाम के करीब पहुंच गई। मजदूर एक बार फिर 12 से 16 घंटे काम करने जैसी गुलामी की स्थिति में फंस गया है। आज पूंजी की दुनिया ने पूरे विश्व को बाजार में बदल दिया है। हर चीज बिकने के लिए तैयार है। परंतु इसकी कीमत पूंजी के मालिक ही तय करेंगे। यहां तक कि भारत के किसान अपने खेतों में जो अन्य पैदा करेंगे वह भी किस भाव पर बिकेगा, यह महाजन ही तय करेगा और यह हो भी रहा है। जिन किसानों की पहुंच मंडियों तक नहीं है, उनके उत्पाद महाजनों के रहमोकरम पर है।

सन 1940 में संयुक्त राष्ट्र की तरफ से मानव अधिकारों पर सार्वभौम घोषणा पत्र जारी

किया गया था। भारत भी उसका एक सदस्य है, जिस पर यह घोषणा पत्र बाध्यकारी है, जिसमें लिखा गया है कि मजदूरी इतनी होनी चाहिए कि जिससे मजदूर और उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। उसी साल हमारे यहां न्यूनतम मजदूरी कानून बनाया गया था। समय–समय पर न्यूनतम मजदूरी का पैमाना बदलता और बढ़ता रहा है। वर्तमान में देश में न्यूनतम मजदूरी 350 रू. से लेकर 523 रू. तक कौशल के हिसाब से 4 कोटियों में अनुमन्य है। लेकिन इस कानून में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें परिवार शब्द गायब है। संविधान के अनुच्छेद 43 जहां मजदूरी की बात आती है वहां पर भी परिवार नहीं है। चूंकि परिवार शब्द नहीं है इसका परिणाम यह हुआ कि मजदूरों के लिए जो भी मजदूरी तय की जाएगी, उसे तय करने के और सारे कारक हो सकते हैं, पर इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि एक मजदूर को कम से कम इतनी कमाई होनी चाहिए कि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। आज देश में असंगठित क्षेत्र के लगभग 12 करोड़ परिवार है। इनमें से ज्यादातर गांव में है जो इस असमानता के खिलाफ बेबस और लाचार हैं। सरकार के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों के अनुसार असंगठित क्षेत्र के हर परिवार के दो लोगों को काम करना पड़ता है। सरकार एक आदमी की मजदूरी इतनी भी तय करने के लिए तैयार नहीं है कि एक आदमी कमाए और पूरा परिवार खाए जो कि मानवाधिकार के तहत अनिवार्य है। इसका मतलब यह है कि व्यावहारिक रूप में दिन–ब–दिन मजदूरी बढ़ने की बजाय घटती जा रही है और असमानता बढ़ती जा रही है। हालांकि संगठित क्षेत्र में मजदूरों को ज्यादा मजदूरी मिलने लगी है। लेकिन वहां अस्थाई नौकरिया घटने लगी है अधिकांश सरकारी संस्थानों में भी संविदा के आधार पर ठेके के लोग रखे जाने लगे हैं। वहां स्थाई कामगारों की तुलना में ठेके के कार्मिकों को बहुत कम सुविधाएं उपलब्ध होती है।

असंगठित क्षेत्र की बात करते हुए वर्तमान में सबसे प्रमुख मानदंड मनरेगा को कहा जा सकता है जिसके तहत काम करने वाले को मजदूरी के रूप में विभिन्न राज्यों में 210 रू. से लेकर 228 रू. रोज प्राप्त होता है। अर्जुन सेन गुप्ता समिति ने अपनी रपट में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 49 रू. प्रतिदिन मजदूरी की सिफारिश की थी। मनरेगा के कानून में 60 रू. प्रति कार्य दिवस लिखा गया। व्यवहार में 100 रू. से शुरू किया गया था जो अब अलग–अलग राज्यों में 210 रू. से लेकर 228 रू. तक पहुंचा है। इसे देखकर कई बार आशंका पनपती है की साजिश के तहत पूजी निवेश के लिए पूंजी जुटाने का ही खेल है क्या? क्योंकि पूजी कुल मिलाकर दो तरह से जुटाई जा सकती है या तो टैक्स लेकर या फिर लोगों की मेहनत का मोल कम करके। भारी भरकम तनख्वाह पाने वाले संगठित क्षेत्र के लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि उनकी पगार का बड़ा हिस्सा सरकार टैक्स के रूप में ले लेती है। वह कहते हैं अच्छा होता कि सरकार टैक्स काट कर के ही उनकी पगार देती। यहां एक सवाल विचारणीय हो सकता है कि सरकार मजदूरों को संतोषजनक मजदूरी अदा करे और बाद में उन पर थोड़ा बहुत टैक्स लगाकर उन्हें राहत दे सकती है क्या। भारत जन आंदोलन के अध्यक्ष रहे डॉ ब्रह्मदेव शर्मा ने इस पर काम किया था तथा उनका आकलन था कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का शोषण आम बात है। उन्होंने अपने अध्ययन में यह अनुमान लगाया था कि लगभग एक करोड़ रुपए, प्रति गांव, प्रतिवर्ष, मजदूरों से शोषण हो रहा है।

देश में आजादी का अमृत काल चल रहा है। पिछले 75 साल से देश का मजदूर काम कर रहा है। विकास के लिए पूंजी जुटाने के खेल में मजदूरों का शोषण हो रहा है जिसका सबसे ज्यादा शिकार असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। इस शोषण के साथ–साथ विकास का जो हमारा पूंजीवादी ढांचा है, उसमें मजदूरों की जरूरत भी धीरे–धीरे खत्म हो रही है। आज अधिकांश काम मशीन से किया जाने लगा है ऐसे में मजदूरों के लिए पारंपरिक कृषि क्षेत्र ही एकमात्र जगह बचती है जहां से वह आजीविका कमा सकता है। मगर इसमें भी साजिश है। अगर हम मनरेगा के तहत दी जा रही मजदूरी की तुलना करें तो किसान इस स्थिति में नहीं है कि वह उसके बराबर भी मजदूरी देकर अपने खेतों में काम करा सके। क्योंकि खेती से उसके पास इतनी बचत नहीं है कि वह दे सकें। यही कारण है कि अधिकांश किसान खेती से भी भागने लगे हैं।

देश के लगभग 40 करोड मजदूरों में 95 प्रतिशत मजदूर असंगठित क्षेत्र के हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए न तो काम के घंटे निर्धारित है और ना ही कोई वेतन आयोग है। उनके लिए न तो काम की निश्चिता है और ना ही भविष्य निधि पेंशन की कोई व्यवस्था उनके लिए न कोई नियम कानून है नहीं सामाजिक सुरक्षा और नहीं काम करने का कोई सही माहौल। उनके हित के लिए बने किसी भी सरकारी कानून को ठीक से लागू नहीं किया जाता। मजदूर के खिलाफ समूचे देश में एक तरह से शोषण का साम्राज्य कायम है। उनके लिए लोकतंत्र का राज और आजादी का अमृत महोत्सव होने का कोई मतलब नहीं है। वह आज भी उतने ही शोषित हैं जितना पहले के दौर में थे। आजादी के अमृत काल के दौरान केंद्र की सरकार द्वारा 80 करोड़ को लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराना इस बात की तस्दीक करता है। ❑❑

# बेरोजगारी दूर करने का दमखम है कृषि में

कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह देश ने प्रवासी मजदूरों का घर–वापसी पलायन देखा, उसके बाद आई आवधिक श्रमिक बल सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि खेत मजदूरों की संख्या में 3 फीसदी का इजाफा हुआ है, यह गिनती वर्ष 2018–19 में 42. 5 प्रतिशत से बढ़कर 2021–22 में 45.5 फीसदी हो गई। जिस कृषि क्षेत्र को इन तमाम सालों में जान–बूझकर दीन–हीन बनाकर रखा गया है, वह आज भी 40.66 लाख करोड़ रुपये मूल्य का सकल मूल्य संवर्धन (ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए) की कूवत रखता है। यह आंकड़ा इस क्षेत्र की मजबूती और लचीलापन दर्शाता है। और कुछ नहीं, अगर कृषि क्षेत्र में सिर्फ मूल्य समानता ही बना दी जाए अर्थात् उच्चतर कीमत की गारंटी, तो कृषि क्षेत्र कहीं ज्यादा बेहतर कर दिखाए, उत्पादन और मूल्य–संवर्धन, दोनों में।

कृषि उत्पाद की कीमतें नीचे रखने की वजह से जाहिर है कृषि क्षेत्र से होने वाली आय कम दिखाई देती है। इस तथ्य को स्वीकार करने की बजाय बड़ी चालाकी से यह दलील देकर आभास दिया जाता है 'चूंकि देश की कुल आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा केवल 19 प्रतिशत है, इसलिए जो बोझ इसको जिलाए रखने में ढोना पड़ रहा है, उसमें खासी कटौती की जानी चाहिए।' विद्रूपता भरी यह दलील पुरानी पड़ चुकी आर्थिक सोच का दोहराव है, जो किसानों को खेती से बाहर धकेलने को आमादा है। मुख्यधारा के अर्थशास्त्री उस वैश्विक आर्थिक साजिश को आगे बढ़ाए रखना जारी रखे हुए हैं जो कृषि की बलि चढ़ाने को आतुर है ताकि आर्थिक सुधारों को व्यवहार्य बनाया जा सके। इसे बदलना ही होगा।

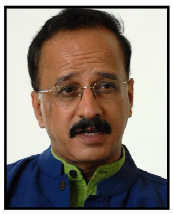

*एक जीवंत खेती व्यवस्था में इतनी ताकत है कि देश के दरपेश रोजगार संकट को अपने भीतर समा सके। दरअसल कृषि बोझ होने की बजाय एक संकटमोचक है।*

**– देविन्दर शर्मा**

आईए, पहले ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट (जीवीओ यानी सकल उत्पादन मूल्य) को समझें। अगर किसी वस्तु की औसत कीमत बढ़ती है तो उसकी ग्रॉस वैल्यू (सकल मूल्य) में भी बढ़ोतरी होती है। विकसित देश इस समीकरण का इस्तेमाल करके भारत की ताड़ना करते हैं कि वह विश्व व्यापार संगठन समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। गेहूं और चावल के न्यूनतम खरीद मूल्य में बढ़ोतरी के साथ, अमीर विकसित देश किसी उत्पाद के कुल मूल्य का निर्धारण उत्पादन को कीमत से गुणा करके निकालते हैं। फिर इससे यह हिसाब लगाते हैं कि भारत एग्रीगेट मेजरमेंट ऑफ सपोर्ट (सकल माप समर्थन फार्मूले) के तहत 10 प्रतिशत सब्सिडी देने की तयशुदा सीमा से कितना ऊपर जाकर कृषकों को राहत देता है। अन्य शब्दों में, वे यह गणना करते हैं कि भारत उत्पाद के कुल मूल्य का कितना हिस्सा कृषि क्षेत्र को बतौर सहायता प्रदान करता है। बात यह है कि यदि उत्पादन पहले जितना रहे और कीमत ऊपर उठती है तो उसका जीवीओ भी ऊपर जाएगा।

परंतु, क्योंकि हम कृषि उत्पाद की कीमतें कम रखते हैं लिहाजा जीवीओ भी नीचे बना

रहता है। वर्तमान में, जिंस की खेत में लगने वाली कीमत सामान्यतः नीचे रहती है, यहां तक कि घोषित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य से 20–30 से फीसदी कम। गेहूं और चावल, और कुछ हद तक कपास, कुछेक दालों और चंद सब्जियों के अलावा थोक मूल्य नीचे ही रहता है। मुझे मालूम है कि उत्पाद के सकल मूल्य का निर्धारण चंद मंडियों में लगने वाली तात्कालिक कीमत का औसत निकालकर, फिर इसमें अन्य कुछ खर्च जोड़कर, तय किया जाता है। तार्किक यह है कि अगर बाजार मूल्य बनिस्बत ऊंचा रहे, जो कि घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम न हो, तब जीवीओ भी तुलानात्मक रूप से ऊंचा रहेगा।

साल 2014–15 में कर्नाटक सरकार ने किसानों को तुअर दाल पर 450 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया, नतीजतन रिकॉर्ड खरीद हुई। इस प्रक्रिया में, तुअर दाल उत्पादक की आय में 22,500 रुपये की अतिरिक्त वृद्धि हुई। कल्पना करें कि यदि देशभर में तुअर दाल की कीमतों में इतने स्तर की वृद्धि हो जाती तो इस जिंस विशेष की जीवीओ कहीं ज्यादा हो जाती। इसी प्रकार, गेहूं का मौजूदा न्यूनतम खरीद मूल्य, जो कि इस साल 2125 रुपये प्रति क्विंटल है, यदि उसको देशभर में कानूनन गारंटी से लागू कर दिया जाए तो न केवल पंजाब–हरियाणा बल्कि पूरे देश के किसान को उच्चतर मूल्य मिल पाएगा। इससे गेहूं उत्पादन का जीवीओ खुद–ब–खुद काफी उच्च गिना जाएगा। यदि शेष फसलों की कीमतों में आनुपातिक वृद्धि कर दी जाए तो यही बात उन पर भी लागू होती है।

जो अन्य पैमाना अर्थशास्त्री लागू करते हैं, वह है ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए (सकल मूल्य संवर्धन)। जीवीए और जीवीओ के बीच अंतर यह है कि फसल उगाने में आई लागत और कच्चे माल की कीमत को जीवीओ से घटाना पड़ता है। वर्ष 2021–22 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग (एनएसओ) ने कृषि, वानिकी एवं मतस्य पालन से हुए जीवीओ की गणना 50.71 लाख करोड़ रुपये की है। इस बात के मद्देनज़र कि कृषि क्षेत्र के जीवीए–जीवीओ अनुपात देशभर में सबसे अधिक यानी 80.19 प्रतिशत है, यहां तक कि जमीन–जायदाद, व्यावसायिक एवं वित्तीय सेवाएं, होटल और व्यापार क्षेत्र से भी अधिक, तो यह बताता है कि कृषि क्षेत्र की उत्पादकता कितनी अधिक है।

कुछ अर्थशास्त्रियों की सोच है कि क्योंकि कृषि के उत्पादन करने में औद्योगिक वस्तुओं की खपत वैश्विक औसत से कम होती है, मसलन, खाद, कीटनाशक और कृषि–उपकरण और उत्पादन का आंकड़ा ज्यादातर भूमि स्रोतों पर आधारित है, सो खेती का जीवीए अधिक रहता है। फिर क्या हुआ? कृषि यदि बाहरी औद्योगिक चीजों का कम इस्तेमाल करने बावजूद इतनी उत्पादकता दे रही है तो कल्पना करें कि यदि सभी 23 फसलों से शुरुआत करके, न्यूनतम खरीद मूल्य को कानूनन रूप से लागू करते हुए, जिंस का उच्चतर और गारंटीशुदा मूल्य बना दिया जाए तो भारतीय कृषि की तस्वीर एकदम बदल जाएगी और यह आर्थिक विकास का मुख्य धुरा बन जाएगी।

वैश्विक स्तर पर, दुनिया अब खाद्य व्यवस्था के रूपांतर की ओर बढ़ रही है, जिसका मंतव्य है कृषि से पैदा होने वाले ग्रीन हाऊस उत्सर्जन को कम करना। इसके लिए ऐसी कृषि–पर्यावरणीय खेती व्यवस्था की ओर जाने की जरूरत पड़ेगी जो कम बाहरी संसाधनों का इस्तेमाल करती हो। मुख्यधारा के अर्थशास्त्रियों को यह जरूर मालूम होना चाहिए कि जैव विविधता तंत्र ने वर्ष 2030 तक कीटनाशकों के उपयोग में दो–तिहाई कटौती करने का आह्वान किया है। यहां पर उनके लिए सबक है।

किसी भी सूरत में, जो बात एकदम शीशे की तरह साफ है कि राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा मुख्यतः इसलिए कम बना रहा क्योंकि किसानों को इन तमाम सालों में उनके हक का बनता मूल्य मिलने से महरूम रखा गया है। यदि कृषि का जीवीए देशभर में सबसे अधिक निकलकर आ रहा है तो मुझे उस बात में तर्क समझ नहीं आता जब अर्थशास्त्री कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था पर बोझ समझकर हेय दृष्टि से देखते हैं। तथ्य तो यह है, यह खेती ही है जो अर्थव्यवस्था को चट्टान की तरह मजबूती दिए हुए है। यहां तक कि जब कोरोना लॉकडाउन के बाद पहली तिमाही में देश की आर्थिकी में 24 प्रतिशत की सिकुड़न दर्ज हुई थी, तब कृषि ही एकमात्र क्षेत्र था जिसने बहुत बढ़िया कर दिखाया था। वास्तव में यह कृषि का निरंतर अच्छा प्रदर्शन ही है जिसने उम्मीदें जिलाए रखी हैं।

एक जीवंत खेती व्यवस्था में इतनी ताकत है कि देश के दरपेश रोजगार संकट को अपने भीतर समा सके। दरअसल कृषि बोझ होने की बजाय एक संकटमोचक है। आज जब देश में कुल जनसंख्या का 45.5 फीसदी कृषि क्षेत्र में कार्यरत है, तो जोर इस ओर देने की जरूरत है कि खेती से चलने वाली आजीविका को आर्थिक रूप से व्यवहार्य और मुनाफादायक बनाया जाए। कृषि क्षेत्र को जानबूझकर सार्वजनिक निवेश से महरूम रखना, किसानों को न्यूनतम खरीद मूल्य की गारंटी न देना और एक भरोसेमंद मंडी व्यवस्था न बनाने को समय की मांग बना दिया गया है। इसके निदान के लिए मौजूदा आर्थिक सोच को पलटने की जरूरत है। ❑❑

*लेखक कृषि एवं खाद्य मामलों के विशेषज्ञ हैं।*
*https://www.dainiktribuneonline.com/news/comment/agriculture-has-the-power-to-remove-unemployment-147585/*

# वन नेशन - वन राशन कार्ड

भारत में गत दो वर्ष से वन नेशन–वन राशन कार्ड़ योजना देश के सभी राज्य व केन्द्रशासित प्रदेशों में शुरू की गई है जिसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे है। देश भर में लगभग 80 करोड़ राशन कार्ड़ धारी है। इस योजना के लागू होने से लगभग 20 करोड़ राशन अपात्र लोगों ने बनाये हुए पाये गये अर्थात अभी तक दो लाख करोड़ रुपये की खाद्यान्न सब्सिडी में से 50 हजार करोड रुपये का खाद्यान्न अपात्र लोग प्रयोग कर रहे थे। सरकार को मिली यह सफलता अमूल्य है। इस योजना से भ्रष्टाचार भी कुछ कम अवश्य हुआ है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लगभग 77 करोड़ से अधिक लाभार्थी देश में पीड़ीएस (पब्लिक ड़ीश्ट्रिब्यूशन सिस्टम) के अंतर्गत देश की राशन की दुकानों से जुड गये है। इस देश में इस योजना के अंतर्गत सभी राशन की दुकानों में कम्प्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है जिसका सबसे ज्यादा लाभ यह मिला है कि समय पर उपयुक्त एवं पात्र उपभोक्ताओं को राशन का लाभ मिल जाता है। दूसरे सरकारी धन का बंदर बांट भी बहुत कुछ कम हुआ है।

वन नेशन–वन राशन कार्ड़ का सर्वाधिक लाभ प्रवासी मजदूरों का मिला है। इस योजना में राज्य के अंदर ही एक शहर व गांव से अन्य शहर एवं गांव में जाने वालों मजदूरों को मिला है। वहीं राज्य से पलायन करने वालें को भी इसका लाभ मिला है। यह योजना लोकप्रिय भी हुई है तथा 60 करोड़ से अधिक बार इस योजना में लेनदेन हो चुका है। पीडीएस को ड़िजिटल बनाने से खाद्य सब्सिड़ी का दुरुपयोग रुक सका है। रोजगार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्यों को जाने वाले श्रमिकों ने एक करोड़ से अधिक बार लेनदेन किया है अर्थात अपनी मूल राशन की दुाकन की अपेक्षा दूसरे राज्य की राशन की दुकानों से सामान खरीदा गया है। सरकार के द्वारा गरीबों को राहत देकर भ्रष्टाचार पर प्रभावी लगाम लगायी गई है।

इस भ्रष्टाचार विरोधी योजना को लागू करने में कुछ प्रदेशों ने नकारात्मक रुख अपना रखा है तथा योजना को लागू करने में राजनीति शुरु कर दी गई है। कुछ राज्यों ने इस

*वन नेशन वन राशन कार्ड़ योजना से स्थानीय और विदेशी लोगों की नागरिकता का निर्धारण होने के साथ ही यह भी जनकल्याण की इस उपयोगी योजना से जुड़ जायेगा।*

**– डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल**

योजना को लागू करने में ढिलाई दिखायी तथा दिल्ली, बंगाल, छत्तीसगढ़ ने इस योजना पर राजनीति करते हुए अपने अपने प्रदेश में योजना को लागू ही नहीं किया। इस मामले में देश के उच्चतम न्यायालय के द्वारा दखल करने पर भी इस योजना को कुछ राज्यों ने नहीं अपना कर देश की इस योजना को लागू करने से ही इंकार कर दिया। इससे राजनीतिक संकीर्णता ही दिखाई दी। देश में इस योजना को नहीं लागू करने वाले राज्यों ने यह दिखा दिया कि गरीबों के हितैषी होने का मात्र दिखावा करते हैं तथा वे गरीबों के हितैषी होने एवं दिखने का ध्यान रखने वाले लोग अपनी ही सरकार में गरीबों के हितों की पूर्ति में बाधक बने हुए है। राज्य और केन्द्र यदि एक दिशा में कार्य करें तो देश का विकास भी तेज हो सकता है तथा गरीब लोगों का कल्याण भी हो सकता है।

इस योजना से मजदूरों, कामगारों और गरीबों की भौगोलिक बाधा भी दूर हो सकी हैं कुछ राजनीतिक दल जो स्वंय को देश के संघीय ढ़ांचे को सशक्त करने की जरुरत दिखाते है वे ही अक्सर इसके खिलाफत करते पाये गये है। वन राष्ट्र वन टैक्स जैसी जीएसटी को लागू करते समय संघवाद के प्रति और अधिक सहयोग भाव दिखाया जाना चाहिए था परन्तु कुछ दलों का स्वर एकदम बदला हुआ था। आयुष्मान योजना एवं नीट के मामले में भी कुछ राज्यों ने सहयोग नहीं दिया। कुछ राजनेता राष्ट्रभाव की भी उपेक्षा कर क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने से भी चुकते है। क्षेत्रीय दलों में अधिक संकीर्णता देखी जा रही है। अब कांग्रेस जैसा राष्ट्रीय दल भी कभी कभी क्षेत्रवाद को उकसाता रहता है।

वन नेशन वन राशन कार्ड़ योजना से स्थानीय और विदेशी लोगों की नागरिकता का निर्धारण होने के साथ ही यह भी जनकल्याण की इस उपयोगी योजना से जुड़ जायेगा। यह योजना बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है तथा गरीब, मजदूर व प्रवासी मजदूर इस योजना का लाभ उठा रहे है। कोरोना काल के भंयकर संकट के समय इस योजना की उपयोगिता अद्वितीय थी। देश में सभी राज्यों में यह स्वीकार कर अच्छे मानसिक सोच के साथ इसको लागू किया जाना चाहिए तथा इस बात पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए कि अन्य देशों से आये घुसपैठिये इस योजना का लाभ उठा कर भारतीयों के हक को तो नहीं ड़कार सकें तथा इस योजना के पात्रों की समय समय पर नियमित जांच प्रक्रिया से गुजार कर परख कर लेनी चाहिए कि पात्र गरीब लोगों को ही इस योजना का लाभ मिले। ❑❑

*डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल सनातन धर्म महाविद्यालय मुजफ्फरनगर 251001 (उ.प्र.), के वाणिज्य संकाय के संकायाध्यक्ष व ऐसोसियेट प्रोफेसर के पद से व महाविद्यालय के प्राचार्य पद से अवकाश प्राप्त हैं तथा स्वतंत्र लेखक व टिप्पणीकार है।*


## :: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
**http://swadeshionline.in/**

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

***सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–***

| *स्वदेशी पत्रिका* | *वार्षिक* | *आजीवन* |
|---|---|---|
| **हिन्दी** | 150 रुपए | 1500/– रुपए |
| **अंग्रेजी** | 150 रुपए | 1500/– रुपए |

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

**स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22**

# क्यों बंद हो रहे परमाणु ऊर्जा के संयंत्र?

**जबसे** रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दोनों देशों की ओर से लगातार परमाणु बम का खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले और अभी भी उत्तर कोरिया, चीन, ईरान और पाकिस्तान की तरफ से परमाणु बम के डर के साये में दुनिया जी रही है। कुछ आक्रांता देश परमाणु बम को ही अपने अस्तित्व के लिए सुरक्षित मान रहे हैं और दूसरे देशों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसी परस्थिति में विश्व यह भी समझने को मजबूर है कि परमाणु बम और परमाणु ऊर्जा विश्व के अस्तित्व के लिए ही सबसे बड़े खतरे के रूप में दिख रहे हैं और सभी परमाणु सम्पन्न देश अपने देशों में परमाणु ऊर्जा संयंत्र और परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न पावर बंद करने पर विचार कर रहे हैं। परमाणु बम और नाभिकीय प्रदूषण उच्च ऊर्जा कणों या रेडियोधर्मी पदार्थों के उत्सर्जन के परिणाम एक जैसे हैं। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण सम्मेलनों विशेषकर कॉप 27 और पूरे विश्व में पर्यावरण प्रेमियों, कार्यकर्ताओं और आंदोलनकारियों ने सभी देशों को पर्यावरण के नष्ट होने के कारणों पर चेतावनी दी है।

वायुमंडल पर रेडियोधर्मिता का प्रभाव परमाणु ईंधन चक्र और परमाणु दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप होता है। जापान के फुकुशीमा के 2011 में परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विस्फोट ने विश्व की चिंता बढ़ा दी है जिसके कारण जापान के सुनामी एवं भूकंप प्रभावित फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में लगी आग एवं उससे हो रहे विकिरण के खतरे के बाद परमाणु दुर्घटनाओं का स्तर 7 तक पहुँच गया है जो परमाणु दुर्घटनाओं का सबसे ज्यादा खतरनाक स्तर है। दुनिया को परमाणु आपदा का एहसास पहली बार वर्ष 1945 में ही हो गया था जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागाशाकी जैसे जापान के दो बड़े शहरों पर क्रमशः 6 तथा 9 अगस्त को द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान परमाणु बम गिराये थे। इस तबाही में लगभग 2 लाख लोग तुरंत मारे गये थे तथा पूरा शहर नष्ट हो गया। इससे झुलसे तथा घायल लोग जीवन पर्यन्त इस पीड़ा को झेलने के लिये विवश थे। उनके बाद की पीढ़ियों को भी इसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ रहा है।

वर्ष 1979 में अमेरिका के थ्री–माइल आइलैंड में स्थित नाभिकीय संयंत्र में हुई दुर्घटना तथा चेरनोबिल (यूक्रेन), जो उस समय सोवियत रूस का हिस्सा था, के परमाणु विद्युत संयंत्र में वर्ष 1986 में हुई दुर्घटनाओं में वायुमंडल में रेडियोधर्मी विकिरण का अत्याधिक प्रभाव देखा गया था, जिसके प्रभाव अभी भी शेष हैं। परमाणु दुर्घटनाओं में जीवों के अलावा निर्जीव पदार्थों को भी विपरीत प्रभाव देखने में आया है। चेरनोबिल दुर्घटना के बाद कम्प्यूटरों में वायरस फैल गये थे। भारत में भी लगभग 10 हजार कम्प्यूटर प्रभावित हुए थे जबकि दक्षिणी कोरिया एवं तुर्की जैसे देशों ने लगभग 3 लाख कम्प्यूटरों के खराब होने की जानकारी दी थी। यह पूरे विश्व के लिये खतरा बना हुआ है। इससे दुनिया भर में परमाणु संयंत्रों को लेकर चिंता हो गयी है।

दिनांक 12 अप्रैल 2023 को इकनॉमिक टाइम्स ने विभिन्न देशों द्वारा बंद किए जाने वाले परमाणु संयंत्रों की सूची दी है। अभी भी 31 देशों में परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिजली उत्पादन में उपयोग हो रहे हैं। जर्मनी ने अपने 3 परमाणु संयंत्रों को बंद करने का निर्णय लिया है। इटली ने पहले ही परमाणु ऊर्जा का उत्पादन बंद कर दिया है। स्विट्ज़रलैंड ने भी परमाणु संयंत्रों को बंद करने का निर्णय लिया है। चीन ने परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण पर रोक लगाई है। भारत ने 90 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा उत्पादन पर रोक लगाई है और जापान ने 15,358 मेगावाट के 17 परमाणु संयंत्रों मे उत्पादन रोक दिया है।

*किसी भी देश के लिए ऊर्जा प्रबंधन बहुत बड़ी चुनौती है। परमाणु ऊर्जा का उत्पादन एक साथ बंद करना संभव न भी हो तो भी परमाणु संयंत्रों का प्रबंधन अचूक होना चाहिए और अक्षय ऊर्जा ही देश की उन्नति, संसाधनों के सदुपयोग, पर्यावरण की सुरक्षा, किसी भी वायुमंडलीय और पर्यावरणीय संकट से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सर्वश्रेष्ठ है।*

**–विनोद जौहरी**

परमाणु संयंत्रों के बंद होने के वैज्ञानिक कारणों को भी जानना आवश्यक है। नाभिकीय प्रदूषण उच्च ऊर्जा कणों या रेडियोधर्मी पदार्थों का उत्सर्जन है जिससे हवा, पानी या भूमि पर मानव या प्राकृतिक जीव–जन्तु प्रभावित हो सकते हैं। रेडियोधर्मी कचरा आमतौर पर नाभिकीय प्रक्रियाओं जैसे नाभिकीय विखंडन से पैदा होता है। इसमें रेडियोधर्मी कणों का लगभग 15 से 20 प्रतिशत हमारे वायुमंडल के स्ट्रैटोस्फीयर में प्रवेश कर जाता है। नाभिकीय प्रदूषण या विस्फोट के कण या विस्फोट के प्रभाव का पेड़–पौधों की पत्तियों और ऊतकों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ये पत्तियाँ खाने वाले पशुओं और इन पर निर्भर रहने वाले जीवों के लिये खतरनाक होती हैं। इनमें रेडियोधर्मी आयोडीन खाद्य–शृंखला के जरिये मानव शरीर में प्रवेश कर जाती है। इससे इंसान में थायराइड का कैंसर हो सकता है। नाभिकीय अवपात का लंबी अवधि तक वातावरण में रह जाना जीव–जन्तुओं के लिये खतरनाक होता है। नाभिकीय विस्फोट एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का परिणाम होता है। इसके फलस्वरूप काफी मात्रा में न्यूट्रॉन अभिवाह उत्पन्न होता है। इस तरह के विस्फोट में रेडियोधर्मी उत्पाद शामिल हैं उदाहरण के तौर पर अप्रयुक्त विस्फोटक यू–235, एवं पीयू–239, तथा विस्फोट से प्राप्त विखंडित उपोत्पाद जैसे स्ट्रॉशियम–90, आयोडीन–131 और सीजियम–137 हैं। विस्फोट बल और तापमान में अचानक वृद्धि इन रेडियोधर्मी पदार्थों को गैसों में परिवर्तित कर देता है और अधिक या कम कणों के रूप में वातावरण में बहुत ऊँचाई तक चले जाते हैं। विखंडन बम की तुलना में संलयन बम के मामले में ये कण कहीं ज्यादा ऊँचाई तक चले जाते हैं। इसका तात्कालिक परिणाम विस्फोट–स्थल पर एक प्राथमिक वातावरणीय प्रदूषण के रूप में होता है तथा इसका द्वितीयक प्रभाव नाभिकीय अवपात के रूप में होता है। इन रेडियोधर्मी पदार्थों का प्रभाव वर्षों तक वायुमंडल में बना रहता है।

| *देश* | *बिजली उत्पादन (मेगावाट)* | *परमाणु संयंत्रों की संख्या* |
|---|---|---|
| अमरीका | 94,718 | 92 |
| फ्रांस | 61,370 | 56 |
| चीन | 53,170 | 56 |
| रूस | 27,727 | 37 |
| दक्षिण कोरिया | 24,489 | 25 |
| जापान | 16,321 | 17 |
| कनाडा | 13,624 | 19 |
| यूक्रेन | 13,107 | 15 |
| स्पेन | 7,121 | 7 |
| स्वीडन | 6,935 | 6 |
| भारत | 6,795 | 22 |
| इंग्लैंड | 5,883 | 9 |
| फ़िनलेंड | 4,394 | 5 |
| जर्मनी | 4,055 | 3 |
| यूएई | 4,011 | 3 |
| **कुल 32 देश** | **3,77,795** | **422** |

(स्रोत : इकनॉमिक टाइम्स 12.04.2023)

एक सीमा के बाद रेडियोधर्मिता से जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव विकिरण की भेदन क्षमता एवं परमाणु स्रोत की अवस्थित पर निर्भर करता है। अधिक भेदन क्षमता वाली गामा विकिरण अन्य के मुकाबले बहुत नुकसानदायी होती हैं। बीटा विकिरण शरीर के अंदरूनी अंगों पर अधिक प्रभाव डालते हैं जबकि अल्फा विकिरण त्वचा द्वारा रोक लिये जाते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण गर्भ में पल रहे शिशु का मौत तक हो सकती है।

उच्च–स्तर परमाणु कचरा आम तौर पर एक परमाणु रिएक्टर या परमाणु हथियार के कोर से प्राप्त सामग्री होते हैं। इस कचरे में यूरेनियम, प्लूटोनियम और अन्य अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व जो विखंडन के दौरान प्राप्त होते हैं, शामिल होते हैं। इन उच्च–स्तर अपशिष्ट पदार्थों में अधिकांश रेडियो समस्थानिक बड़ी मात्रा में विकिरण उत्सर्जित करते हैं और इनकी आयु बहुत लंबी (कुछ की 1 लाख साल से भी ज्यादा) होती है और इन्हें रेडियोधर्मिता के सुरक्षित स्तर पर पहुँचने के लिये लंबी समयावधि की आवश्यकता होती है। इन्हें विशेष स्टील के कंटेनरों में रखकर गहरे समुद्र में डाल देते हैं। इन कंटेनरों का जीवन 1000 वर्ष होता है। चूँकि उच्च–स्तर परमाणु कचरे में अत्यधिक रेडियोधर्मी विखंडन उत्पाद और दीर्घजीवी भारी तत्व है इसलिये यह काफी मात्रा में ऊष्मा पैदा करता है जिससे निपटने के लिये परिवहन के दौरान इसे ठंडा रखने और विशेष परिरक्षण की आवश्यकता होती है। इस तरह देखा जाए तो नाभिकीय प्रदूषण का प्रबंधन किसी देश के लिये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है।

किसी भी देश के लिए ऊर्जा प्रबंधन बहुत बड़ी चुनौती है। परमाणु ऊर्जा का उत्पादन एक साथ बंद करना संभव नहीं भी हो तो भी परमाणु संयंत्रों का प्रबंधन अचूक होना चाहिए और अक्षय ऊर्जा ही देश की उन्नति, संसाधनों के सदुपयोग, पर्यावरण की सुरक्षा, किसी भी वायुमंडलीय और पर्यावरणीय संकट से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सर्वश्रेष्ठ है। आज जितना निवेश परमाणु संयंत्रों, परमाणु हथियारों पर संपूर्ण विश्व में हुआ है उतना निवेश विश्व में निर्धनता को समाप्त करने के लिए पर्याप्त था। जिन देशों की अर्थव्यवस्था यूरेनियम तथा अन्य रेडियोधर्मी खनिज के खनन, प्रोसेसिंग और निर्यात पर निर्भर है, उनकी आर्थिक और पर्यावरणीय चिंता भी आवश्यक है। ❑❑

*विनोद जौहरी, सेवानिवृत्त अपर आयकर आयुक्त*

# ईएसजी को प्रभावित करता है एआई!

ईएसजी यानी पर्यावरण, सामाजिक और शासन से संबंधित वह दृष्टिकोण है जो आज नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, कॉरपोरेटस और अन्य हितधारकों के बीच व्यापक चर्चा में है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर,) सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) और पर्यावरण प्रभाव आकलन (आईए) की व्यवस्था पहले से मौजूद है, लेकिन ईएसजी इससे कुछ अलग हटकर किया गया उपबंध है। ईएसजी केवल सामाजिक रुप से जिम्मेदार व्यवसाय नही है बल्कि स्थाई व्यवसायिक प्रथाओं को अपनाने का एक व्यापक तरीका है। निवेशक व्यवसाय की दीर्घकालिक स्थिरता के साथ साथ इससे जुड़े किसी भी जोखिम की पहचान करने के लिए ईएसजी विश्लेषण पर अधिक भरोसा कर सकते हैं।

सीएसआर, ईआईए और एसआईए का दायित्व कंपनी पर है जबकि ईएसजी हितधारकों के अत्यंत करीब है। एक बढ़िया ईएसजी अभ्यास एक संगठन की विश्वसनीयता को बनाए रखने में मदद करता है। जबकि ईएसजी से इतर वाला संगठन जिसमे सीएसआर,एस आईए,ईआईए आदि भी शामिल है, अस्थिरता उच्च जोखिम और लंबी अवधि में अचानक नुकसान के लिए महत्वपूर्ण क्षमता के जोखिम पर चलता है। ईएसजी निवेश के लिए पर्यावरण प्रभाव और प्रदूषण या कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए किसी भी प्रयास को संदर्भित करता है। इसमें समुदाय के आसपास का भी संबंध जैसे परोपकार और कॉरपोरेट नागरिकता भी शामिल है। दूसरी तरफ शासन शेयर धारकों के अधिकार, मुआवजे तथा मैनेजमेंट और शेयर धारकों के बीच संबंध के लिए भी जिम्मेदार है। आज की दुनिया में ईएसजी सभी व्यवसायों पर लागू हुआ है और कंपनिया इसके योगदान को महसूस भी कर रही हैं। अधिक से अधिक निवेशकों, शेयर धारको कर्मचारियों, ग्राहकों, नियामको के साथ प्रणाली में अधिक पारदर्शिता के लिए क्लीमेरिंग ईएसजी अनिवार्य हो रहा है। ऐसे में केवल सीएसआर अथवा एस आईए या ईआईए के बल पर पृथ्वी ग्रह के भविष्य की चुनौतियों से नहीं निपटा जा सकता है। ईएसजी निवेश दुनिया के साथ साथ भारत में व्यवसाय के तरीके को बदल सकता है तथा व्यापार समुदाय के साथ–साथ पूरी मानवता की मदद कर सकता है।

*आज बैंक, आपूर्ति श्रृंखला उपभोक्ता जरूरतें सभी कुछ के लिए बड़ी कंपनियों द्वारा ईएसजी का अभ्यास किया जा रहा है। ऐसे में हमें सरकार और आम लोगों की भागीदारी से कृत्रिम मेघा को भी विनियमित करने की जरूरत है।*

**–आलोक कुमार सिंह**

इस ऑफ डूइंग बिजनेस और नियामकों की भूमिका के बीच संबंध को नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में उच्च रैंकिंग के व्यवसाय पर नियामकों के नियंत्रण में भी कमी नहीं आनी चाहिए। व्यापार करने में आसानी और नियामकों के नियंत्रण के बीच व्यापार को शून्य राशि के खेल के रूप में नहीं देखा जा सकता। व्यापार सुगमता के लिहाज से लाइसेंस परमिट राज्य का अनुभव खराब रहा है। व्यापार सुगमता और नियामकों के बीच लाभकारी रिश्ते होने चाहिए। ऐसे में समाज, पर्यावरण और शासन को व्यवसाय मॉडल में एक सक्रिय भागीदार बनाने के लिए विकेंद्रीकरण का रास्ता अनुकूल हो सकता है।

आजकल बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,एआई) कारोबार को नियंत्रित करने की दौड़ में है। उन्हें अनुसंधान करने, डेटा विश्लेषण करने और एआई कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए सर्वोत्तम मानव संसाधनों की आवश्यकता है। लेकिन विडंबना है कि इसी दौर में सिलीकान वैली की बड़ी प्रौद्योगिक कंपनियों में बड़े पैमाने में छंटनी भी हो रही है। यह परस्पर विरोधी बातें हैं जिसे समझने की जरूरत है। एक तरफ कंपनियां गतिशीलता, मनोरंजन, शिक्षा, खरीदारी, विज्ञापन, चुनाव प्रचार और यहां तक की समाचार के क्षेत्र में एआई के जरिए भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ इन कंपनियों द्वारा की जा रही भारी छंटनी इस बात का संकेत दे रही हैं कि एआई एक संक्रमण के चरण में है जो प्रत्येक सक्षम राष्ट्र के लिए विघटनकारी स्थितियां पैदा करने के करीब हैं। भविष्य की प्रौद्योगिकी के लिए एआई अपने नियम गढ़ रहा है। एआई से जुड़ी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों का उद्देश्य केवल भारी मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि वह

**आज हम एक दिलचस्प चौराहे पर खड़े हैं, जहां एआई आने की जल्दी में है और बड़ी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने को बेताब है। ठीक उसी समय ईएसजी सभी हितधारको के दरवाजे खटखटा रही हैं।**

मनुष्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना चाहती है। किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में भाग लिए बिना दुनिया को काबू में रखने का वे ख्वाब रखती है। बड़े पैमाने पर हो रही छटनी से संकेत मिलता है कि वे ऐसी नई प्रतिभा की तलाश में हैं जो विघटनकारी एआई पर काम कर सके। ऐसे में जब तक उन्हें वांछित प्रतिभा मिल नहीं जाती एआई की गति कमोबेश बाधित ही रहेगी।

आज हम एक दिलचस्प चौराहे पर खड़े हैं, जहां एआई आने की जल्दी में है और बड़ी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने को बेताब है। ठीक उसी समय ईएसजी सभी हितधारको के दरवाजे खटखटा रही हैं। ई–कॉमर्स, क्रिप्टो करेंसी, सोशल मीडिया के दुरुपयोग, फर्जी समाचार, कर चोरी, टीकाकरण कार्यक्रम, खाद्य सुरक्षा, व्यापार नीति, मनी लॉन्ड्रिंग और विभिन्न प्रकार के वित्तीय गैर वित्तीय भ्रष्टाचार को विनियमित करने के लिए नियामक एजेंसियां समर्थन कर रही हैं। भ्रष्टाचार एक मानसिकता है, जिसे पूरी तरह खत्म करने के लिए कोई भी कानून पुख्ता नहीं है। लेकिन दूसरे हाथ में हमारे पास कोविड–19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए आरोग्य सेतु एप, डिजिटल लेनदेन, सबको घर जैसे कार्यक्रम की सफलता की कहानियां भी है। चाहे गति शक्ति हो अथवा रक्षा उत्पादों में भारत की आत्म निर्भरता हो, वंदे भारत जैसी सेमी बुलेट ट्रेन डिजाइन करना हो, एयरक्राफ्ट बनाने की क्षमता हो, या प्रौद्योगिकी का कार्यक्रम हो, दुनिया हमारा लोहा मानने लगी है। हमारे कदम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विकेंद्रीकरण, स्थानीयकरण, सहकारिता और स्वरोजगार हमारे जनसांख्यिकी लाभांश के उपयोगी होने की कुंजी है। पेप्सी और कोको–कोला का उपयोग हमारे लिए मजबूरी नहीं है बल्कि हमारे लोगों में जागरूकता की कमी का नतीजा है। हमारी प्रगति समाज, पर्यावरण, जीवन शैली और हितधारकों की परिभाषा पर लोगों के नियंत्रण के दर्शन से मेल खाती है। विकेंद्रीकरण और सहकारिता हमारे समाज में सदियों से मौजूद है। ऐसे में इएसजी को लोगों द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए। सरकार के भरोसे हम इसे नहीं छोड़ सकते। हमारे पास ओटीटी बनाम टीवी चैनलों के उदाहरण है। ओटीटी तकनीक का लाभ है और जब तक सरकार इसे नियमित करने के लिए तंत्र विकसित करेगी एआई के जरिए कोई अन्य विकारी तकनीक पाइप लाइन में होगी।

भारत सरकार ने क्रिप्टोकरंसी को नियंत्रित करने में सफलता पाई है। जीएसटी के जरिए कर संग्रह का ईमानदार तंत्र विकसित किया है। इसी तर्ज पर प्रभावकारी सरकारी नीति और लोगों की भागीदारी द्वारा एआई को विनियमित किया जा सकता है। आज बैंक, आपूर्ति श्रृंखला उपभोक्ता जरूरतें सभी कुछ के लिए बड़ी कंपनियों द्वारा ईएसजी का अभ्यास किया जा रहा है। ऐसे में हमें सरकार और आम लोगों की भागीदारी से कृत्रिम मेघा को भी विनियमित करने की जरूरत है। ❑❑

# कल के लिए जरूरी है बेहतर जल प्रबंधन आज

भारत जल के वैश्विक स्त्रोतों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पूरी दुनिया में भारत में पानी का सर्वाधिक इस्तेमाल (13 प्रतिशत) होता है। भारत के बाद चीन (12 प्रतिशत) और अमेरिका (9 प्रतिशत) का स्थान है। जैसे–जैसे पानी का उपभोग बढ़ता है, देश पानी के अभाव की समस्या से जूझता है। पानी के उपभोग की मात्रा किसी देश के नागरिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में खर्च होने वाले पानी की मात्रा से तय होती है। आमतौर पर किसी देश या क्षेत्र विशेष में पानी की उपलब्धता की वस्तुस्थिति का पता लगाने के लिए स्वीडन के जल विशेषज्ञ प्रो. मैलिन फॉकनमार्क द्वारा बनाए गए मानकों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अनुसार यदि शोधन योग्य पानी का वार्षिक स्रोत प्रति कैपिटा 1700 से 1000 प्रति क्यूबिक मीटर है तो इसका अर्थ है कि वहां पानी की स्थिति दबावपूर्ण है। 1000 क्यूबिक मीटर से कम होने पर पानी का अभाव समझा जाता है। अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (आईडब्ल्यूएमआई) ने एक नक्शा बनाया है कि दुनिया में कहां–कहां पानी के अभाव की स्थिति है। मध्य एशिया और उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश देश पानी के अभाव से ग्रस्त हैं। ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, पाकिस्तान, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और पश्चिमी अमेरिका भी जलाभाव के संकट को महसूस कर रहे हैं।

भारत में बहुत सी नदियों (कावेरी, सिंध नदी का जो हिस्सा हिंदुस्तान में है, कृष्णा, माही, पेनार, साबरमती और ऊपरी पश्चिमी क्षेत्र में बहने वाली नदियां) में पानी कम हो गया है। गोदावरी और ताप्ती नदी जलाभाव की स्थिति की ओर बढ़ रही हैं, जबकि गंगा, नर्मदा और सुवर्णरेखा जैसी नदियों को तुलनात्मक जलाभाव की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस समय ब्रह्मपुत्र, मेघना, ब्रह्मणी, वैतरणी और महानदी आदि ऐसी नदियां मानी जाती हैं, जिनमें अतिरिक्त जल है। आईडब्ल्यूएमआई की हाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक बहुत सी भारतीय नदियों में पानी का संकट होगा। भारत को प्रतिवर्ष वर्षा, बर्फ और ऊपरी सीमा पर स्थित पहाड़ी देशों से बहकर आने वाली नदियों से औसतन 4000 खरब क्यूबिक मीटर

*नई पीढ़ी को पानी के मामले में ज्यादा मुश्किल भविष्य का सामना करने के लिए तैयार करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि इस समय इन चुनौतियों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।*

**– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र**

जल प्राप्त होता है। हम अमूमन शोधन योग्य जल स्रोतों जैसे नदियों और जमीन के अंदर स्थित जल की बात करते हैं, जो 1869 खरब क्यूबिक मीटर है। एक अनुमान के मुताबिक किसी स्थान के भौतिक अवरोधों और वर्षा की भिन्नता के कारण प्रतिवर्ष अधिकतम 1123 खरब क्यूबिक मीटर पानी (शोधन योग्य जल का 60 प्रतिशत) का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 690 खरब क्यूबिक मीटर सतह का और 432 खरब क्यूबिक मीटर जमीन के भीतर का पानी है। वर्षा का शेष 53 प्रतिशत पानी मिट्टी में जम जाता है या वायुमंडल में वाष्प बनकर उड़ जाता है, पौधों और वनस्पतियों द्वारा ग्रहण किया जाता है या जमीन के बहुत गहरे से बहकर समुद्र में मिल जाता है।

भारत में 4525 बड़े बांध हैं, जिनकी संग्रह क्षमता 220 खरब क्यूबिक मीटर है। इसमें जल संग्रह के छोटे–छोटे स्रोत शामिल नहीं हैं, जिनकी क्षमता 610 खरब क्यूबिक मीटर है। फिर भी हमारी प्रति कैपिटा संग्रहण की क्षमता ऑस्ट्रेलिया, चीन, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन और अमेरिका से बहुत कम है। चूंकि वर्ष में एक निश्चित समय तक (लगभग 100 दिन) वर्षा होती है, इसलिए वर्ष के बाकी सूखे दिनों के लिए पानी को संग्रहित करके रखना बहुत जरूरी है। जो लोग बड़े बांधों के विरोधी हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि टैंक और रोधक बांध समेत पानी के संग्रह के हर छोटे और बड़े स्रोत की किसी क्षेत्र के जल संकट को हल करने में अपनी भूमिका है और उसे दूसरों के प्रतियोगी या विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

भारत में जल संकट को दूर करने के रास्ते में चार मुख्य चुनौतियां हैं। पहला सार्वजनिक सिंचाई नहरों की सिंचाई क्षमता में इजाफा, कम हो रहे भूमि जल संग्रह को पुनः संग्रहित करना,

**वर्ष में एक निश्चित समय तक वर्षा होती है, इसलिए वर्ष के बाकी सूखे दिनों के लिए पानी को संग्रहित करके रखना बहुत जरूरी है। जो लोग बड़े बांधों के विरोधी हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि टैंक और रोधक बांध समेत पानी के संग्रह के हर छोटे और बड़े स्रोत की किसी क्षेत्र के जल संकट को हल करने में अपनी भूमिका है और उसे दूसरों के प्रतियोगी या विकल्प के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।**

प्रति यूनिट पानी में फसलों की उत्पादकता में वृद्धि और भूमिगत और जमीन के ऊपर के जल स्रोतों को नष्ट होने से बचाना। पूरी दुनिया में कृषि में पानी का सर्वाधिक अपव्यय होता है। अब इस बात का काफी दबाव है कि इस मांग को कम करके घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की तेजी से बढ़ रही मांग को पूरा किया जाए और पर्यावरण के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाए। खेतों में डालते और ले जाते हुए जो पानी बर्बाद होता है, वह पानी की वास्तविक बर्बादी नहीं है। पानी की बर्बादी को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है, लाभदायक और गैर लाभदायक। रिसाव के कारण बर्बाद होने वाला पानी लाभदायक हो जाता है, यदि वह भूमिगत जल में मिल जाए और कुंओं के द्वारा पुनः इस्तेमाल में आए। कुछ जल विशेषज्ञों के मुताबिक विश्व में वास्तव में जल संकट नहीं है, बल्कि पानी के गलत प्रबंधन के कारण दुनिया को उसकी कमी से जूझना पड़ रहा है। भारत में जल संकट का कारण जुझारू कोशिश और सही सोच का अभाव है। जाने– माने जल विशेषज्ञ और स्टॉकहोम वॉटर प्राइज विजेता प्रो. असित बिस्वास के मुताबिक, 'गुजरे 200 वर्षों के मुकाबले आने वाले 20 सालों में जल प्रबंधन के काम और प्रक्रियाएं ज्यादा बड़े परिवर्तनों के दौर से गुजरेंगे।' दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण इक्कीसवीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को बहुत तेजी से पुरानी व्यवस्था को बदलना चाहिए और नई व्यवस्था अपनानी चाहिए। नई पीढ़ी को पानी के मामले में ज्यादा मुश्किल भविष्य का सामना करने के लिए तैयार करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि इस समय इन चुनौतियों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। ❑❑

# दो ट्रिलियन निर्यात की बड़ी छलांग

मार्च 31, 2023 को घोषित विदेश व्यापार नीति के अनुसार वर्ष 2030 तक 2000 अरब डालर के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात शामिल हैं। देश में अभी तक निर्यातों के ढुलमुल प्रदर्शन के चलते, कई विशेषज्ञ इस बड़े लक्ष्य के बारे में शंका व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ देश में विशेषज्ञों का एक बड़ा वर्ग इस लक्ष्य को असाध्य नहीं मान रहा। बल्कि कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि देश इससे कहीं ज्यादा प्राप्त कर सकता है। दोनों पक्षों के क्या तर्क हैं, इसे समझना होगा।

आज से दस साल पहले 2012–13 में भारत के वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात मात्र 452.3 अरब डालर के ही थे। 2012–13 के बाद हमारे आयात तो द्रुत गति से बढ़ते गए, लेकिन निर्यातों के बढ़ने की गति धीमी रही।

2021–22 में हमारे वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात हालांकि 683.7 अरब डालर तक पहुंच गए थे, लेकिन आयात 766 अरब डालर पहुँच गए। लेकिन हालांकि आयात इस वर्ष 882 अरब डालर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि निर्यात भी पिछले वर्ष 683.7 अरब डालर की तुलना में, इस वर्ष 767.0 अरब डालर रह सकते हैं। यह सही है कि पिछले 10 वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात बहुत तेजी से नहीं बढ़े। लेकिन पिछले साल वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात 11.3 प्रतिशत की दर से बढ़ गए।

यानि कुछ समय पहले जो 2030 में निर्यातों का 1000 अरब डालर का लक्ष्य भी अभेद्य लग रहा था, 2023 में 2000 अरब डालर का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु देश को निर्यातों के बढ़ने की गति को मात्र 14.81 प्रतिशत ही रखना होगा, जो कि पिछले वर्ष में निर्यातों की ग्रोथ से बहुत ज्यादा नहीं है।

## अर्थव्यवस्था की स्थिति

आज जब भारत समेत दुनिया के सभी मुल्क बढ़ती महंगाई से त्रस्त हैं, भारत में महंगाई की दर शेष दुनिया से अभी भी कम है। भारत लगातार दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। बढ़ती ग्रोथ का असर जीएसटी की प्राप्तियों में दिखाई दे रहा है। हालांकि जीएसटी प्राप्तियों में बड़ा हिस्सा आयात शुल्कों का है, लेकिन मध्यवर्ती वस्तुओं के आयातों पर मूल्य संवर्द्धन भी जीएसटी में वृद्धि का कारण बन रहा है। यानि ग्रोथ हो या महंगाई

*वर्ष 2013–14 में भारत की अर्थव्यवस्था मात्र 2 खरब डॉलर से भी कम थी, जो अभी तक बढ़कर 3.5 खरब डॉलर से ज्यादा हो चुकी है। वर्ष 2030 में जब हम 7 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन चुके होंगे, 2 खरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है।*
**–स्वदेशी संवाद**

पर अंकुश सभी देश की बढ़ती निर्यात संभावनाओं की और इंगित कर रहे हैं।

## कैसे बढ़ सकते हैं निर्यात?

यह भी सही है कि दुनिया में चल रही मंदी और महंगाई के कारण घटती क्रय शक्ति के चलते निर्यातों में वृद्धि करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। उसके बावजूद भारत के सेवाओं और वस्तुओं के निर्यातों में हो रही वृद्धि विशेष महत्व रखती है। देखना होगा कि भारत के निर्यातों में कहां ज्यादा वृद्धि हो रही है।

खाद्य पदार्थों के निर्यात में वृद्धि का कुल निर्यातों में विशेष योगदान है। 2021–22 में 50 अरब डालर से अधिक खाद्य निर्यात किए गए। 2022–23 के आंकड़े आना अभी बाकी है, लेकिन अभी भी खाद्य निर्यातों में कुल निर्यातों में खासा योगदान बना हुआ है।

निर्यातों में वृद्धि में प्रतिरक्षा निर्यातों का बड़ा योगदान दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि अभी तक भारत प्रतिरक्षा के क्षेत्र में आयातों पर ही अधिक निर्भर रहा है। लेकिन प्रतिरक्षा उद्योग में हुई प्रगति और विशेषतौर पर निजी क्षेत्र के प्रतिरक्षा उद्योग में बढ़ते योगदान के चलते देश न केवल प्रतिरक्षा में उपकरणों में आत्मनिर्भर हुआ है, बल्कि इस उद्योग का निर्यातों में भी योगदान बढ़ा है। एक ओर जहां देश अपनी प्रतिरक्षा जरूरतों का 70 प्रतिशत आयातों से प्राप्त करता था, अब मात्र 32 प्रतिशत उपकरणों के लिए ही आयातों पर निर्भर करता है और 68 प्रतिशत प्रतिरक्षा खरीद भारत से हो रही है।

पिछले 6 वर्षों में प्रतिरक्षा निर्यातों में 10 गुणा से ज्यादा वृद्धि, भविष्य में इस क्षेत्र के निर्यातों की संभावना को इंगित करती है। गौरतलब है कि 2016–17 में प्रतिरक्षा निर्यात मात्र 1521 करोड़ रूपए के थे, जो 2022–23 में बढ़कर 15920 करोड़ रूपए तक पहुंच चुके हैं। कहा जा सकता है कि भारत का प्रतिरक्षा उद्योग एक ओर विदेशी मुद्रा बचा रहा है और दूसरी ओर विदेशी मुद्रा कमा भी रहा है। बढ़ते विदेशी आर्डरों से प्रतिरक्षा उद्योग में काफी स्पंदन दिखाई दे रहा है।

सेवा क्षेत्र में भारत का परचम पिछले 30 वर्षों से लहरा ही रहा है, लेकिन वर्तमान काल में उसका महत्व और बढ़ गया है। 5 वर्षों में ही हमारे सेवाओं के निर्यात 2016–17 में 164.2 अरब डालर से बढ़ते हुए 2021–22 तक 254.5 अरब डालर तक पहुंच गए थे। वर्ष 2022–23 के पहले 11 महीनों में ये निर्यात 296.9 अरब डालर तक पहुंच चुके हैं और अनुमान है कि 2022–23 के पूर्ण वर्ष के लिए यह आंकड़ा 325 अरब डालर पार कर सकता है। खास बात यह है कि इन निर्यातों में आधे से ज्यादा हिस्सा सॉफ्टवेयर निर्यातों का है। इसके अलावा देश बड़ी मात्रा में बीपीओ, एलपीओ समेत कई प्रकार की व्यवसायिक सेवाओं का भी निर्यात कर रहा है। देश की सॉफ्टवेयर में प्रगति ने चीन समेत अन्य मुल्कों को भी पीछे छोड़ रही है।

## रूपए में व्यापार से भी बदल सकती है तस्वीर

दुनिया के कई मुल्क भारत से आयात करना चाहते भी थे तो भी वे पूर्व में डॉलरों के अभाव के चलते आयात नहीं कर पाते थे। लेकिन हाल ही में भारत सरकार ने एक पहल की और भारतीय रिजर्व बैंक ने एक परिपत्र के माध्यम से आयात और निर्यात के लिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान निपटारों को रूपयों में करने की अनुमति प्रदान कर दी। इसके बाद दिसंबर में पहली बार रूस के साथ व्यापार का भुगतान रूपयों में करने की शुरूआत हो चुकी है। अभी तक भारत सरकार के प्रयासों से इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जर्मनी, मलेशिया, इजराइल, रूस और युनाईटेड अरब अमीरात समेत 19 देशों के बैंकों को 'स्पेशल वोस्त्रो रूपी एकाउंट' खोलकर रूपयों में भुगतान निपटारे करने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि रूपयों में भुगतान होने के कारण जहां पहले आयात के लिए डॉलर, पाउंड, येन इत्यादि का उपयोग होता था, वे भुगतान रूपयों में होने लगेंगे। इन 19 मुल्कों के साथ अभी भी काफी बड़ी मात्रा में आयात और निर्यात होता है, रूपयों में भुगतान के चलते इन मुल्कों के पास भारतीय रूपए का स्टॉक बढ़ेगा और वे भारत से ज्यादा सामान आयात कर सकेंगे।

## बेहतर होती प्रतिस्पर्धा शक्ति

पूर्व में भारतीय साजो–सामान दुनिया के दूसरे मुल्कों की तुलना में महंगा माना जाता था, उसका कारण था हमारी इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी। पिछले कुछ समय से देश में बिजली की अब कोई कमी दिखाई नहीं देती। उद्योगों को निरंतर बिजली मिल रही है। सौर ऊर्जा इत्यादि के कारण बिजली की लागत में भी कुछ कमी देखने को मिल रही है। सड़कों के जाल बिछने के कारण अब आवाजाही आसान हो गई है। बेहतर डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर भी भारत की प्रतिस्पर्धा को बेहतर बना रहा है।

ऐसे में जब अभी तक भारत 767 अरब डालर के निर्यात का लक्ष्य हासिल कर चुका है, अगले 7 वर्षों में निर्यात को 2000 अरब डालर तक ले जाना कोई अभेद्य लक्ष्य नहीं लगता। लेकिन देश को इसके लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बल देना होगा, लागतों को कम करना होगा और वर्तमान में इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण की गति को बरकरार रखना होगा। गौरतलब है कि वर्ष 2013–14 में भारत की अर्थव्यवस्था मात्र 2 खरब डॉलर से भी कम थी, जो अभी तक बढ़कर 3.5 खरब डॉलर से ज्यादा हो चुकी है। वर्ष 2030 में जब हम 7 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बन चुके होंगे, 2 खरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। ❑❑

# वैश्विक स्तर पर भारतीय सबसे अधिक प्रसन्नता प्राप्त करने की ओर अग्रसर

अभी हाल ही में वर्ष 2023 के लिए वैश्विक प्रसन्नता प्रतिवेदन (ग्लोबल हप्पीनेस रिपोर्ट 2023) जारी किया गया है। वैश्विक प्रसन्नता प्रतिवेदन को, 150 से अधिक देशों का विभिन बिंदुओं पर सर्वे करने के उपरांत, संयुक्त राष्ट्र दीर्घकालिक विकास समाधान तंत्र द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वैश्विक प्रसन्नता प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के पूर्व, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक सहयोग, भ्रष्टाचार का स्तर, समाज में नागरिकों के बीच आपसी सदाशयता एवं निर्णय लेने की स्वतंत्रता जैसे बिंदुओं पर विभिन्न देशों का आंकलन किया जाता है। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन एवं नॉर्वे जैसे छोटे छोटे देश जिनकी जनसंख्या तुलनात्मक रूप से बहुत कम रहती है, इस सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। उक्त सर्वे के अनुसार सबसे अधिक प्रसन्न देश, फिनलैंड में केवल 55 लाख नागरिक निवास करते हैं, डेनमार्क में 58.6 लाख लोग रहते हैं एवं आइसलैंड में तो महज 3.73 लाख नागरिक ही निवास करते हैं। इसके विपरीत भारत के अकेले मुम्बई, दिल्ली, कोलकता, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद जैसे शहरों की जनसंख्या इन देशों की उक्त वर्णित जनसंख्या से कई गुना अधिक है। वैसे विश्व के विभिन्न देशों के नागरिकों की प्रसन्नता को एक जैसे 6 अथवा 7 बिंदुओं पर सर्वे करते हुए नहीं आंका जा सकता है। क्योंकि, प्रत्येक देश के नागरिकों में खुशी अथवा गम की अवस्था अलग अलग कारकों एवं कारणों के चलते भिन्न भिन्न होती है।

*भारत के नागरिकों का आध्यात्म एवं धर्म की ओर झुकाव भी उन्हें विपरीत परिस्थितियों के बीच भी संतुष्ट एवं प्रसन्न रहना सिखाता है। इसी मुख्य कारण से भारत प्राचीन काल में विश्व गुरु रहा है। और, अब पुनः भारत, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो चुका है, इससे भी भारत के नागरिकों में प्रसन्नता की स्थिति का निर्माण होना बहुत स्वाभाविक ही है।*

**– प्रहलाद सबनानी**

वैश्विक प्रसन्नता प्रतिवेदन के माध्यम से जारी सूची में भारत को 126वां स्थान दिया गया है। परंतु, आश्चर्य तो इस बात पर है कि लगातार आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याओं से जूझ रहा पाकिस्तान इस सूची में 103वें स्थान पर है। इस आंकलन के अनुसार, क्या पाकिस्तान के नागरिक, भारत के नागरिकों की अपेक्षा अधिक प्रसन्न हैं? इसी प्रकार, इस सूची में चीन को 64वां, नेपाल को 78वां, बांग्लादेश को 118वां एवं श्रीलंका को 112वां

स्थान दिया गया है। जबकि, श्रीलंका, बांग्लादेश एवं नेपाल भी लगातार आर्थिक समस्याओं से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैश्विक प्रसन्नता प्रतिवेदन के माध्यम से जारी सूची में शीर्ष 20 देशों में एशिया का कोई भी देश शामिल नहीं है। अर्थात, केवल यूरोपीय देशों के नागरिक ही प्रसन्न रहते हैं, जबकि एशिया से चीन विश्व की दूसरी, जापान विश्व की तीसरी एवं भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अर्थात, विश्व की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में तीन एशिया के देश हैं, परंतु फिर भी एशिया के नागरिक प्रसन्न नहीं हैं? उक्त वैश्विक प्रसन्नता प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिए जाते समय सम्भवतः कुछ बुनियादी गलतियां हुई होंगी, ऐसा आभास होता है। क्योंकि, उक्त सर्वे के साथ ही इसी संदर्भ में तीन अन्य सर्वे भी जारी हुए हैं, जिनके परिणामों में भारतीय नागरिकों को बहुत प्रसन्न बताया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग द्वारा भी अभी हाल ही में विभिन्न देशों में नागरिकों की प्रसन्नता को आंकने के संदर्भ में एक सर्वे किया गया है। यह सर्वे मुख्य रूप से वित्तीय क्षेत्र में प्रसन्नता, कार्य स्थल पर पहुंचने एवं उत्पादकता से सम्बंधित प्रसन्नता, मानसिक प्रसन्नता, जीवन एवं कार्य के बीच संतुलन, ऊर्जा की उपलब्धता, आदि जैसे बिंदुओं पर आधारित है। यह सर्वे 61 देशों के सम्बंध में उक्त वर्णित मानदंडों पर प्राप्त विस्तृत जानकारी के आधार पर सम्पन्न किया गया है।

वित्तीय क्षेत्र में प्रसन्नता को आंकते समय देश में सकल बचत, शुद्ध बचत एवं निजी साख ब्यूरो कवरेज का ध्यान रखा गया है। बचत एवं ऋण की आसान उपलब्धता को भी वित्तीय प्रसन्नता को आंकने के मापदंड में शामिल किया गया है। वित्तीय प्रसन्नता के मापदंड

**प्रत्येक देश में कर्मचारियों को वेतन के साथ उपलब्ध कराए जा रहे अवकाश की संख्या को भी कर्मचारियों में प्रसन्नता को आंकने हेतु उपयोग किया गया है। इस प्रकार किए गए आकलन के अनुसार सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है एवं इराक को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को 45वां स्थान प्राप्त हुआ है।**

पर कतर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ग्रीस को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है एवं भारत को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है।

कार्य स्थल पर पहुंचने एवं उत्पादकता से सम्बंधित प्रसन्नता को आंकते समय कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र से अलग अलग जानकारीयां प्राप्त की गई है। देश में फसल उत्पादन सूचकांक के आधार पर किसानों की प्रसन्नता को आंका गया है। देश में व्यापार करने में आसानी (ईज आफ डूइंग बिजनिस) सूचकांक के आधार पर उद्योग क्षेत्र में कार्य कर रहे नागरिकों की प्रसन्नता को आंका गया है। कर्मचारियों की उत्पादकता को आंकने हेतु मानव पूंजी सूचकांक का उपयोग किया गया है। देश में बेरोजगारी की दर बढ़ने से नागरिकों में नकारात्मक भाव जागृत होता है, इसे आंकने का प्रयास भी किया गया है। प्रत्येक देश में कर्मचारियों को वेतन के साथ उपलब्ध कराए जा रहे अवकाश की संख्या को भी कर्मचारियों में प्रसन्नता को आंकने हेतु उपयोग किया गया है। इस प्रकार किए गए आकलन के अनुसार सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है एवं इराक को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को 45वां स्थान प्राप्त हुआ है।

देश में मानसिक प्रसन्नता को आंकने के लिए नागरिकों में विषाद की स्थिति को आंका गया है एवं इन देशों के नागरिकों द्वारा अपना कितना समय परोपकार के कार्यों में लगाया जाता है, इसे भी आंकने का प्रयास किया गया है। इस मापदंड पर इंडोनेशिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है एवं पुर्तगाल को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि भारत 11वें स्थान पर रहा है।

उक्त सर्वे में यह रोचक तथ्य भी उभरकर सामने आया है कि कुछ देशों में जीवन एवं कार्य के बीच संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से इन देशों के नागरिकों द्वारा उस कार्य को किया ही नहीं जाता है जिससे उनके जीवन एवं

कार्य के बीच असंतुलन की स्थिति निर्मित हो। कार्य के कुल समय में कितना लचीलापन है, नौकरी की सुरक्षा, 65 वर्ष के पूर्व सेवा निवृत्ति प्राप्त करना एवं नौकरी से प्रयोजन का हल होना जैसे बिंदुओं को इस मापदंड के अंतर्गत आंका गया है। इस मापदंड को आंकने के लिये केवल 28 देशों की जानकारी प्राप्त हो पाई है। इस मापदंड के अनुसार, भारत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है एवं जापान को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है।

ऊपर वर्णित समस्त मापदंडो को मिलाकर जो 61 देशों के अंतिम परिणाम प्राप्त हुए हैं, उनके अनुसार आस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर रहा है एवं सूडान को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि, भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में प्रथम 10 देश निम्न प्रकार रहे है, आस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, ग्रीस, कनाडा, पोलैंड, जर्मनी, इटली एवं फिनलैंड।

इसी प्रकार, एक परामर्शदात्री संस्थान हैप्पीप्लस द्वारा 'द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस 2023' विषय पर जारी एक प्रतिवेदन के अनुसार, भारत में लगभग 35 प्रतिशत नागरिकों ने वर्ष 2022 में नकारात्मकता और दुख का अनुभव किया है, और शेष 65 प्रतिशत नागरिक अपेक्षाकृत प्रसन्नचित रहे हैं। उक्त प्रतिवेदन भारत के 36 राज्यों एवं केंद्र

**हैप्पीप्लस द्वारा 'द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस 2023' विषय पर जारी एक प्रतिवेदन के अनुसार, भारत में लगभग 35 प्रतिशत नागरिकों ने वर्ष 2022 में नकारात्मकता और दुख का अनुभव किया है, और शेष 65 प्रतिशत नागरिक अपेक्षाकृत प्रसन्नचित रहे हैं।**

शासित क्षेत्रों में निवासरत 14,000 नागरिकों की प्रतिक्रिया जानने के बाद तैयार किया गया है। इसी प्रकार के एक अन्य सर्वे के अनुसार भी भारत में कम से कम 84 प्रतिशत नागरिकों ने अपने आप को प्रसन्न बताया है। 'जीवन संतुष्टि' पर आधारित यह 'इप्सोस ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे' बताता है कि पूरे विश्व में 73 प्रतिशत नागरिक संतुष्ट हैं।

अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने एक बयान में कहा है कि भारत एवं चीन मिलकर, केलेंडर वर्ष 2023 के दौरान होने वाली वैश्विक आर्थिक वृद्धि में, 50 प्रतिशत की भागीदारी करेंगे। कोरोना महामारी एवं रूस तथा यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद में 3 प्रतिशत से कम की वृद्धि दर्ज होगी, जो कि सम्भवतः वर्ष 1990 के बाद से किसी एक वर्ष में सबसे कम वृद्धि दर होने जा रही है। कलेंडर वर्ष 2023 के दौरान भारत एवं चीन को छोड़कर विश्व के अन्य सभी बड़े देशों में आर्थिक वृद्धि दर विपरीत रूप से प्रभावित होने की सम्भावना व्यक्त की गई है। इस प्रकार, जब भारत में आर्थिक विकास बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है तो स्वाभाविक रूप से भारत के नागरिकों में प्रसन्नता का भाव भी बढ़ेगा। वैसे भी, विश्व बैंक ने विशेष रूप से भारत में गरीब वर्ग के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में लगातार हो रहे अतुलनीय सुधार के चलते गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिकों की संख्या में भारी कमी की भरपूर प्रशंसा की है। साथ ही, भारत के नागरिकों का आध्यात्म एवं धर्म की ओर झुकाव भी उन्हें विपरीत परिस्थितियों के बीच भी संतुष्ट एवं प्रसन्न रहना सिखाता है। इसी मुख्य कारण से भारत प्राचीन काल में विश्व गुरु रहा है। और, अब पुनः भारत, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो चुका है, इससे भी भारत के नागरिकों में प्रसन्नता की स्थिति का निर्माण होना बहुत स्वाभाविक ही है। ❑❑

*प्रहलाद सबनानी, सेवा निवृत्त उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, ग्वालियर, म.प्र.*

## :: सूचना ::

**स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।**

**संपादक, स्वदेशी पत्रिका**

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

# सतही होती जा रही है संबंधों की संवेदना

एक बार किसी प्रसिद्ध चित्रकार से एक धनी व्यक्ति ने अपना एल्बम सुधारने के लिए कहा। चित्रकार ने सुधार करके एक हजार रूपए का बिल दे दिया। धनी व्यक्ति ने कहा कि आपने तो इस काम में केवल 5 मिनट ही लगाए हैं और इतने से काम की आप इतनी बड़ी रकम मांग रहे हैं। इसके प्रत्युत्तर में चित्रकार ने कहा, '"हां, आपकी बात ठीक है, लेकिन ऐसे काम को 5 मिनट में किस प्रकार पूरा किया जाता है, यह सीखने के लिए मैंने तीन साल का श्रम किया है।" आज हमें ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है, जो अपने नाम और प्रसिद्धि की तनिक भी परवाह न करते हुए किसी काम को सीखने और पूरा करने में वर्षों का श्रम न्यौछावर कर सकें और उसका उचित परिणाम पाने के लिए प्रतीक्षा भी कर सकें। मिराब्यू ने अपना ग्रंथ पूरा करने के लिए 40 साल निरंतर संघर्ष किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि उसने सारे फ्रेंच साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। माइकल एंजेलो ने वर्षों की मेहनत से रोम में एक गिरजे की साज–सज्जा की, परंतु उसने पारिश्रमिक लेने से इसलिए इनकार कर दिया कि उसकी कूची कहीं धन के लोभ में विकृत न हो जाए। जॉन मिल्टन ने अपनी महत्वपूर्ण कृति 'पैराडाइज लॉस्ट' झाड़ियों के सामने बैठकर लिखी थी।

ऐसे बहुत लोग हैं, जिन्होंने धैर्य और परिश्रम से जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल किया। उन्हें खुद को समाज में स्वीकृत और प्रतिष्ठित करने के लिए वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ी। उन्होंने पैसे को जीवन में कभी भी प्राथमिकता नहीं दी। पैसा एक जरूरत है लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है का संदेश दिया। लेकिन आज दुनिया के साथ–साथ भारतीयों की अभिरुचियां काफी तेजी से बदल रही है। इसलिए भारतीय संबंधों का परंपरागत स्वरूप भी आज काफी संकट की स्थिति में आ गया है। लोगों की व्यस्तता बढ़ गई है और फुर्सत का अभाव पैदा हो गया है। संबंधियों के बीच भौतिक दूरियां बढ़ती जा रही हैं। मोबाइल क्रांति और सोशल मीडिया ने प्रत्यक्ष मगर आभासी मिलन के शक्तिशाली विकल्प उपलब्ध करवा दिए हैं। किसी बड़े शहर में रहने वाले रिश्तेदार और मित्र भी अब महीनों तक एक दूसरे से सीधे नहीं मिल

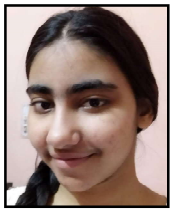

*संबंधों के निर्वाह का ताल्लुक प्रमुख रूप से व्यक्तियों की संवेदनशीलता और उनके संबंधों की सच्चाई और गहराई से है। इसी कारण कई बार मुंहबोले रिश्तों में संबंधों का निर्वाह रक्त–संबंधियों से भी अधिक घनिष्ठता और आत्मीयता के साथ देखा जा सकता है।*
**–वैदेही**

पाते। रोजगार की खोज में बलिया का युवक जाकर बंगलुरु में रहने लगता है और कभी–कभी तो देश की सरहद पार कर किसी दूसरे देश पहुंच जाता है और वहीं का नागरिक हो जाता है। इतनी दूरी से किसी के लिए अपने संबंधों और संबंधियों की परवाह भला कैसे संभव है? हर व्यक्ति आज एक ओर मेहनत से बचना चाहता है तो दूसरी ओर रातोरात करोड़पति हो जाना चाहता है। हमारे समाज की आज की अनेक विकृतियों का मूल इन नई प्रवृत्तियों में ढूंढा जा सकता है।

संबंधों का निर्वाह व्यक्ति से दूसरों के काम आने और उनके लिए कुछ कष्ट उठाने की अपेक्षा रखता है। जो दूसरों द्वारा किए गए उपकार के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, केवल उन्हीं से संबंधों के निर्वाह की उम्मीद की जा सकती है। जो बच्चे अपने माता–पिता द्वारा उनके लालन–पालन के लिए उठाए गए कष्टों को यह कहकर भुला देते हैं कि जब उन्होंने हमें पैदा किया, तब वह कष्ट तो उन्हें उठाना ही था। उन बच्चों से कोई माता–पिता अपनी वृद्धावस्था में किसी आलंबन की अपेक्षा नहीं रख सकते। एक समय वह था जब लोगों के बहुत से काम अन्य लोगों की सहायता के बिना हो ही नहीं सकते थे। आज पैसे से उपलब्ध अधिक साधनों ने उस तरह की अनिवार्य निर्भरता का अंत कर दिया है। इसलिए अब अन्य बातों की परवाह न करते हुए अधिकाधिक पैसा कमाना ही व्यक्ति को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण लगने लगा है। किसी के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति भी आजकल लोग उसके लिए पैसा खर्च करके ही कर देते हैं। माता–पिता के प्रति अपने कर्त्तव्यों की इतिश्री आजकल बहुत–सी संतानें उनके इलाज या उनके लिए जरूरी साधन जुटाने के लिए पैसा खर्च करके कर देती हैं। लेकिन वृद्धावस्था में लोगों को जिस प्रकार के भावनात्मक आलंबन की आवश्यकता होती है, वह पैसे से नहीं मिलता।

**माता–पिता के प्रति अपने कर्त्तव्यों की इतिश्री आजकल बहुत–सी संतानें उनके इलाज या उनके लिए जरूरी साधन जुटाने के लिए पैसा खर्च करके कर देती हैं। लेकिन वृद्धावस्था में लोगों को जिस प्रकार के भावनात्मक आलंबन की आवश्यकता होती है, वह पैसे से नहीं मिलता।**

सार्वजनिक संबंधों पर विचार किया जाए तो हम पाते हैं कि किसी व्यक्ति को दिए जाने वाले महत्त्व और सम्मान के पीछे भी एक सामूहिक कृतज्ञता–भाव रहता है। बुद्ध या महावीर को दिए जाने वाले आदर के पीछे कहीं न कहीं लोगों का वह सामूहिक कृतज्ञता भाव है जो वे इन महापुरुषों की तपस्या द्वारा अर्जित उस ज्ञान के लिए महसूस करते हैं, जिसे उन्होंने उनके मार्गदर्शन के लिए वितरित किया।

संबंधों की दृढ़ता में निस्वार्थता की भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होती है। जब आपसी संबंधों में स्वार्थ की बू आने लगती है तब उसमें निश्चय ही खटास पैदा हो जाती है। स्वस्थ संबंध वही होता है, जिसमें दो व्यक्तियों की निकटता आनंद और भावनात्मक उष्णता का संचार करती हो। यह तभी संभव है, जब ये व्यक्ति एक दूसरे से अपने लिए कुछ करवाने के बजाय एक दूसरे के लिए कुछ करने में खुशी महसूस करें। आपसी संबंधों की गरमाहट और मधुरता को दिल से महसूस करने वालों की संख्या अब तेजी से घट रही है, पर जो लोग उसका मूल्य समझते हैं, वे आज भी उनके निर्वाह का प्रयत्न करते हैं और उसके लिए आवश्यक कष्ट उठाने को तैयार रहते हैं।

परिवार या समाज में पहले हर संबंधी की भूमिका पूर्व निर्धारित रहती थी। लोग यह मान कर चलते थे कि अगर कोई किसी का भाई या शिष्य या पड़ोसी है तो वह उसके प्रति अपने अमुक नैतिक कर्तव्य का पालन तो करेगा ही। जाति, धर्म और पारिवारिक–सामाजिक परंपराएं इन नैतिक कर्तव्यों को परिभाषित भी करती रहती थीं। आज की धर्मनिरपेक्षता और सार्वभौमिकता ने कर्त्तव्य–विमुख होने के लिए किसी अन्य धर्म या अन्य देश की प्रथाओं के हवाले को भी लोगों के लिए संभव बना दिया है। संबंधों का मामला दोतरफा रहता है। बढ़ती आत्मपरकता के आज के समय में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो दूसरों का एहसान तो आसानी से ले लें, पर जो दूसरों के लिए कुछ करने की जरूरत जरा भी न समझें। उनकी तमाम होशियारी के बावजूद ऐसे लोगों के इरादों की पोल खुल ही जाती है।

दरअसल, संबंधों के निर्वाह में आज पैसे की भूमिका प्रमुख होती जा रही है। आज का बच्चा माता–पिता के अपने प्रति प्रेम को उस पैसे से मापता है, जो उन्होंने उसके जन्मदिन की पार्टी पर खर्च किया। आज वही दादा पोते को अधिक सगा लगता है जो उसे विदेश में पढ़ाई के लिए अपने पास से लाखों रुपए देने को तैयार हो जाए। महंगे वस्त्राभूषण, महंगे होटल, महंगे उपहार ही आज संबंधों में घनिष्ठता का पर्याय बनते जा रहे हैं। संबंधों के निर्वाह का ताल्लुक प्रमुख रूप से व्यक्तियों की संवेदनशीलता और उनके संबंधों की सच्चाई और गहराई से है। इसी कारण कई बार मुंहबोले रिश्तों में संबंधों का निर्वाह रक्त–संबंधियों से भी अधिक घनिष्ठता और आत्मीयता के साथ देखा जा सकता है। ❑❑

# ओएनडीसी बना जोमैटो के लिए नई मुसीबत!

इस समय ओएनडीसी की खूब चर्चा है। इस ओपन प्लेटफॉर्म की वजह से जोमैटो की शेयर बाजार में हालात खराब है। निवेशकों को डर है कि ओएनडीसी की वजह से जोमैटो जैसे फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म प्रभावित होंगे। हाल ही में जोमैटो के शेयरों में 5 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है।

ओएनडीसी एक ओपन प्लेटफॉर्म है। जहां कोई भी व्यक्ति सामान खरीद और बेच सकता है। इसके लिए उन्हें किसी एक एप पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यहां ये खाना मंगाने से लेकर शॉपिंग करने तक सब कुछ संभव है। इसे ऑनलाइन शॉपिंग दुनिया का 'यूपीआई' कहा जा रहा है।

जोमैटो शेयर बाजार में 23 जुलाई 2021 को लिस्ट हुई थी। कंपनी के आईपीओ की कीमत 76 रुपये प्रति शेयर तय की गई थी। शेयर बाजार में कंपनी प्रदर्शन बहुत शानदार नहीं रहा है। निफ्टी 50 इंडेक्स में पिछले एक साल में 11 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। वहीं, जोमैटो ने 3.6 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

*https://www.livehindustan.com/business/story-zomato-share-price-falls-5-perent-today-is-it-a-ondc-effect-or-else-8144466.html*

# भारत 2026 तक 64 अरब डॉलर का सेमीकंडक्टर मार्केट हब बन जाएगा

कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और आईटी हार्डवेयर जैसे क्षेत्रों से महत्वपूर्ण मांग के साथ देश का सेमीकंडक्टर मार्केट 2026 तक 64 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट मुताबिक भारत के टेलीकॉम स्टैक के साथ–साथ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस से सेमीकंडक्टर मार्केट के आकार का दो–तिहाई हिस्सा होने की उम्मीद है। 2019 में देश के सेमीकंडक्टर मार्केट का वैल्यूएशन 22.7 अरब डॉलर था। काउंटरपॉइंट के रिसर्च डायरेक्टर तरुण पाठक का कहना है कि शॉर्ट टर्म में सेंसर, लॉजिक चिप्स और एनालॉग डिवाइस जैसे एप्लीकेशंस में घरेलू मांग की ओर संचालित एक बड़ा अवसर है। स्थानीय सोर्सिंग पहले से ही एक महत्वपूर्ण तरीके से हो रही है।

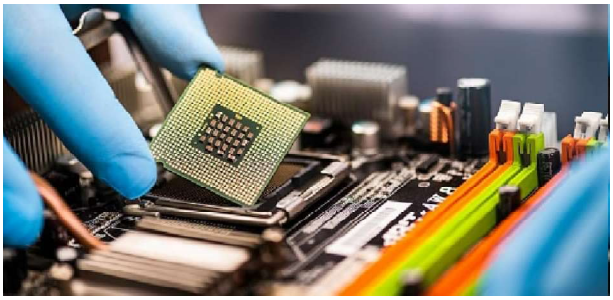

2022 में कुल बाजार में इसका लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा था। भारत के बढ़ते ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण अवसर देखने की उम्मीद है। सरकार ने दिसंबर 2021 में सेमीकंडक्टर्स के डेवलपमेंट और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए 76,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना की घोषणा की थी। पिछले साल सितंबर में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधा की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट लागत के 50 प्रतिशत पर वित्तीय सहायता, सभी टेक्नोलॉजी नोड्स में समान बनाकर प्रोत्साहन को और अधिक किया गया था। इससे पहले विभिन्न यूनिट्स के लिए राजकोषीय समर्थन 30–50 प्रतिशत के बीच था।

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के सीईओ और संयुक्त अमितेश कुमार सिन्हा ने कहा है कि भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक विश्वसनीय भागीदार बनने के लिए प्रतिबद्ध है और अगले 25 वर्षों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक नीतियां बनाकर इस दिशा में काम किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए प्रोजेक्ट लागत का 70 प्रतिशत से अधिक भारत में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें से 50 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा अग्रिम आधार पर वित्त पोषित किया जाता है जबकि शेष राज्य सरकारों द्वारा कवर किया जाता है।

वेदांता–फॉक्सकॉन जेवी, आईजीएसएस वेंचर्स और आईएसएमसी जैसी कंपनियों ने 13.6 अरब डॉलर के निवेश के साथ चिप निर्माण प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है और प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार से 5.6 अरब डॉलर का समर्थन मांगा है।

*https://m.dailyhunt.in/news/india/hindi/punjabkesari-epaper-punjkes/*

# विदेश पढ़ने जा रहे छोटे शहरों और गांव के विद्यार्थी

पिछले साल विदेश जाकर पढ़ाई करने वालों की संख्या 6 साल में सबसे ज्यादा रही। संसद में दिए गए जवाब के अनुसार, 2022 में 7.5 लाख स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए विदेश गए। खास बात यह है कि अब दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों की बजाय देश के छोटे शहरों, कस्बों और गांवों के छात्र

अधिक संख्या में पढ़ने के लिए विदेश जा रहे हैं। इसकी एक वजह देश के अच्छे कॉलेजों में दाखिला न मिल पाना है तो दूसरी वजह मौकों की कमी है। देश में नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्द्धा बढ़ी है। एआई और आईटी जैसे सेक्टरों में विदेशों में ज्यादा मौके हैं। वहां वेतन भी ज्यादा है। इसलिए विद्यार्थी दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं।

देश में जैसे–जैसे विदेशों में पढ़ाई के लिए जाने का ट्रेंड बढ़ रहा है। विदेश जाने में मदद करने वाली कंसल्टेंसीज का बाजार भी बड़ा हो रहा है। देश भर में ऐसी कंसल्टेंसीज खुल रही हैं। पहले छोटे शहरों और कस्बों से कम आय वाले घरों के 30 प्रतिशत बच्चे पढ़ने विदेश जा रहे थे। यह संख्या बढ़कर दोगुनी यानी 60 प्रतिशत हो गई है। ये बच्चे घर या खेती की जमीन बंधक रखकर विदेश जा रहे हैं। इसके साथ ही फ्रॉड के मामले भी बढ़े हैं। अभी हाल ही में कनाडा ने 700 भारतीय बच्चों को डिपोर्ट किया है। उन्हें एजेंट ने फर्जी तरीके से दाखिला दिला दिया था। वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा छात्र अमेरिका और कनाडा गए। अमेरिका–4.65 लाख, कनाडा–1.83 लाख, यूएई–1.64 लाख, ऑस्ट्रेलिया–1 लाख, सऊदी अरब–65 हजार, ब्रिटेन–55 हजार, जर्मनी–35 हजार।

कोरोना की वजह से दुनिया के कई देशों में अब भी चीन के छात्रों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। विदेशों में पढ़ने के लिए

भारतीय छात्रों को सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्द्धा चीनी छात्रों से ही करनी पड़ती है। भारतीय इसे मौके के तौर पर ले रहे हैं।

*https://money.bhaskar.com/national/news/foreign-education-more-students-from-small-towns-and-villages-are-going-to-study-abroad-than-metros-131242656.html*

## भारत में खाद्य महंगाई दर 4.79 फीसदी

देश में इस साल मार्च महीने में खाने पीने की चीजों की महंगाई दर 4.79 फीसदी पर रही है जो इस साल फरवरी में 5.95 फीसदी और मार्च 2022 के 7.68 फीसदी से काफी कम है। देश में महंगाई का ये वो दौर है जब दुनिया के कई देशों में ये आंकड़ा 300 फीसदी से भी ऊपर है। यहां तक कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश की ये महंगाई काफी ऊंची है।

आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में खाने पीने की चीजों की महंगाई 8.5 फीसदी है। वहीं फ्रांस में ये 14.9, ब्रिटेन में 19.1, जर्मनी में 21.2 और पाकिस्तान में 48 फीसदी है। जिम्बाब्वे में ये 102, अर्जेंटीना में 110, वेनेजुएला में 158 और लेबनान में 352 फीसदी से ज्यादा गई है। पूरी दुनिया में ऐसे दौर है जब अमेरिका और यूरोपीय देशों में महंगाई के आंकड़े सहनशीलता की सीमा से काफी ऊपर हैं। दुनिया के ये देश कोरोना महामारी के बाद अपनी अर्थव्यवस्थाओं को खोलने के प्रयास में हैं। साथ ही ये देश रूस–यूक्रेन युद्ध की परिस्थितियों के परिणामों को भी झेल रहे हैं।

महंगाई के तुलनात्मक आंकड़ों को री–ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की एक सदस्य प्रोफेसर शमिका रवि ने कहा, "शाबाश भारत – इतने मुश्किल वैश्विक दौर में खाद्य मुद्रास्फीति को बहुत अच्छी तरह से प्रबंधित करने के लिए। देश में केंद्र सरकार ने खाद्य महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए तमाम कदम उठाए हैं। रूस–यूक्रेन युद्ध को देखते हुए भारत ने पिछले साल ही गेहूं की निर्यात नीति में संशोधन करते हुए इसे निषिद्ध श्रेणी में डाल दिया है। वैश्विक गेहूं की कीमतों ने पिछले वर्ष दुनिया भर में अस्थिरता देखने को मिली थी। यूक्रेन और रूस दोनों ही गेहूं के प्रमुख आपूर्तिकर्ता हैं।

*https://www.livehindustan.com/business/story-food-inflation-rate-in-india-is-less-than-many-countries-then-in-which-country-is-it-the-highest-8143841.html*

## एफएसएसएआई की स्टार रेटिंग की जगह लागू हो वार्निंग सिस्टमः डॉ. अश्वनी महाजन

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने केन्द्र सरकार द्वारा देशी–विदेशी प्रोडक्ट को स्टार रेटिंग की जगह वार्निंग सिस्टम को लागू किए जाने की मांग की है। डॉ. महाजन ने इसे लेकर एक ऑनलाइन याचिका भी दायर की है, जिसमें अभी तक 24 हजार से ज्यादा लोग साइन कर चुके हैं। संगठन का मानना है प्रोडक्ट की स्टॉर रेटिंग की बजाए सरकार को इन पर वार्निंग जारी करनी चाहिए। संगठन की ओर से एक प्रतिनिधि

मंडल ने स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों से भेंट कर स्टार रेटिंग पर अपनी आपत्ति दर्ज करायी है।

दरअसल एफएसएसएआई ने पैकेज्ड फूड पर वार्निंग की जगह सटॉर रेटिंग देने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत खाने पीने के पैकेज्ड फूड पर हेल्थ वार्निंग की जगह स्टॉर रेटिंग होगी। हर तरह के खाने को स्टॉर रेटिंग दी जाएगी। इस रेटिंग में एफएसएसएआई के अनुसार लोगों को ये पता चल पाएगा कि कौन सा खाना स्वस्थ है और कौन का अस्वस्थ। मौजूदा समय में ये व्यवस्था सिर्फ दो देशों 'आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड' में अपनाई जा रही है। आस्ट्रेलिया जैसे देश में तो कई संगठन के इसके साइड इफेक्ट को लेकर अध्ययन भी कर चुके हैं।

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन कहते हैं कि ये व्यवस्था मौजूदा समय में सिर्फ आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही चल रही है। अभी हमारे देश में जो व्यवस्था चल रही है, उसे फ्रंट ऑफ पैकेज्ड लेबलिंग कहते है। एफओपीएल जहां–जहां लांच किया गया है, वहां–वहां हेल्थ वार्निंग दी गई है। इसमें इतना शुगर है, सॉल्ट है, ये सब उपभोक्ता को पता चल जाता है कि वो क्या खा रहा है। जबकि स्टॉर रेटिंग एक तरह से उपभोक्ता को मिसगाइड करने वाली व्यवस्था है। इस व्यवस्था में इस बात की भी संभावना रहती है कि कंपनियां हाई शुगर, और सॉल्ट का इस्तेमाल कर दें। इसकी स्टॉर रेटिंग की भी अपनी–अपनी परिभाषा है, मसलन कोई फाइव स्टॉर इसलिए देता है क्योंकि उसमें फ्रूट एडेड है। बाकी सभी जगह दरअसल इस पूरे सिस्टम के बाजार में आने के बाद आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि आप जिस पैकेट बंद खाने को खा रहे है उसमें क्या कुछ मिला है।

*https://www.bwhindi.com/business-news/swadeshi-jagran-protests-against-star-rating-of-food-products-files-online-petition-55622.html*

# न पूंजीवाद और न ही साम्यवाद, हमें चाहिए राष्ट्रवादः सतीश कुमार

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संगठक श्री सतीश कुमार ने कहा है कि हमें न पूंजीवाद चाहिए और न साम्यवाद, हमें चाहिए राष्ट्रवाद। श्री सतीश कुमार स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत विचार वर्ग एवं स्वावलंबी भारत अभियान की कार्यशाला को मुख्य वक्ता के रूप में मानसरोवर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक दौर था, जब चीन में बारिश होती थी तो साम्यवादी भारत में छाता तान लेते थे, लेकिन आज उनकी स्थिति पूरी तरह बदल गई है। हमें भारत को स्वावलंबी बनाकर युवाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार करना है। उन्होंने कहा कि लोगों को पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी की तलाश होती है। सरकारी नौकरी की तलाश करने

की बजाय हमें उन्हें रोजगार देने वाला बनाना चाहिए।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक बाबूलाल ने कहा कि 16वीं सदी में भारत की जीडीपी 22 प्रतिशत थी, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद भारत की जीडीपी 3 प्रतिशत रह गई। इतिहास के दस्तावेजों में पता चलता है कि भारत की जीडीपी जब 22 प्रतिशत थी, उस समय इंग्लैंड की जीडीपी मात्र 3 प्रतिशत थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें स्वावलंबी भारत बनाने के लिए स्वरोजगार को तवज्जो देनी चाहिए।

मंच के प्रांत संयोजक देवेंद्र भारद्वाज ने कहा कि समय की मांग है कि आज हमे स्वरोजगार के माध्यम से स्वावलंबी होकर भारत को मजबूत राष्ट्र बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने वाला बनना चाहिए। प्रांत प्रचार प्रमुख डॉ धर्मवीर चन्देल ने बताया कि कार्यशाला के अलग–अलग को सत्रों को मंच के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख धर्मेंद्र दुबे, स्वावलंबी अभियान की राष्ट्रीय सह संयोजक अर्चना मीणा, क्षेत्र संयोजक डॉ सतीश आचार्य, मंच के प्रांत सह संयोजक लोकेंद्र सिंह, मनीषा जैमन सहित अन्य पदाधिकारियो ने सम्बोधित किया। मंच संचालन अभियान के संयोजक महेन्द्र शर्मा ने किया।

*https://www.samacharjagat.com/*

# परम्पराओं को पुनर्जीवित कर रहा स्वदेशी जागरण मंचः निम्बाराम

स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना के समय स्वदेशी न व्यवहार में था और न ही विचार में था, परन्तु स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी विचार को जन जन तक पहुंचाया है। यह बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम ने उदयपुर में स्वदेशी जागरण मंच की ओर से तारणा त्रयोदशी पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में कही। तारणा त्रयोदशी पर श्री–अन्न मोटे अनाज के प्रति जागरूकता के लिए प्रदर्शनी और भोजन का आयोजन रखा गया था।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम ने कहा कि विश्व में केवल भारत एक ऐसा देश है जहां वर्ष में विभिन्न ऋतुएं आती हैं और तदनुसार जितने प्रकार के

पौष्टिक फल सब्जियां यहां उत्पन्न होती हैं, विश्व में कहीं नहीं होती। यही कारण है कि भारत जैव विविधता के मामले में सर्वाधिक संपन्न राष्ट्र है।

उन्होंने कहा कि अन्न उपभोग करने से हम स्वस्थ रहेंगे, किंतु आज की युवा पीढ़ी चमक–दमक, पैकिंग और विज्ञापन से प्रभावित होकर अस्वास्थ्यकर डिब्बाबंद खाने को प्राथमिकता देकर रोगों को निमंत्रण दे रही है। उन्होंने श्री–अन्न अर्थात मोटे अनाजों पर कहा कि इनके सेवन से हम कई रोगों से बचा सकते हैं। किसी भी देश की वास्तविक सम्पदा वहां के नागरिक ही होते हैं, अगर नागरिक स्वस्थ होंगे तभी समाज स्वस्थ और सुदृढ़ होगा। कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय संस्कृति की विशालता और शुचिता पर बल देते हुए समलैंगिकता को प्रोत्साहन के प्रयासों का समाज से विरोध करने की अपील भी की।

विशिष्ट अतिथि स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख धर्मेन्द्र दुबे ने बताया कि तारणा त्रयोदशी को स्वदेशी जागरण मंच जैव विविधता के रूप में विगत 11 वर्षों से मना रहा है। मेवाड़ में 13 प्रकार के धान से बने भोजन से तारणा व्रत खोलने की परम्परा रही है। स्वदेशी जागरण मंच अभी युवाओं के स्टार्टअप, स्वालम्बन और रोजगार के बड़े उद्देश्य लेकर भी काम कर रहा है।

मुख्य अतिथि डॉ लाखन पोसवाल ने राष्ट्र ऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी को नमन करते हुए कहा कि मोटे अनाज का चिकित्सा विज्ञान में बहुत महत्व है। गेहूं का प्रयोग शरीर के लिए हानिकारक है, जबकी मोटे अनाजों में शामिल बाजरा बीपी, कॉलेस्ट्रोल, शुगर आदि को नियंत्रित रखता है। विश्व में कोविड के समय सबसे बेहतर टीका भारत का था। वैश्विक स्तर के किफायती वेंटिलेटर अब भारत में बनते हैं। यह पूरे विश्व के लिए आश्चर्य और प्रेरणा का विषय है। विश्व की लगभग सभी बड़ी कम्पनियों के सीईओ भारतीय हैं जो हम सब के लिए गर्व का विषय है।

मंच के प्रान्त संयोजक पुरूषोत्तम शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्र संयोजक सतीश आचार्य ने युवा उद्यमियों,यों जैविक खेती के कृषकों, देशी गौपालकों एवं गुणीजनों का परिचय और अभिवादन किया। कार्यक्रम संयोजक रमन कुमार सूद ने मंचासीन अतिथियों का परिचय कराया। जागरण मंच महानगर संयोजक रमेश पुरोहित ने आभार प्रदर्शित किया। आरंभ में क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया तथा अन्तरराष्ट्रीय यज्ञ दिवस पर आयोजित गायत्री यज्ञ में भाग लिया।

*https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2023/5/4/Swadeshi-Jagran-Manch-reviving-traditions-Nimbaram.php*

# स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत विचार वर्ग व स्वावलंबी भारत अभियान की कार्यशाला

स्वदेशी जागरण मंच का दो दिवसीय प्रांत विचार वर्ग एवं स्वावलंबी भारत अभियान की कार्यशाला 6 व 7 मई को हुई। कार्यशाला में स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संयोजक देवेन्द्र भारद्वाज ने दौसा जिला संपर्क प्रमुख ललित शर्मा बांदीकुई, दौसा नगर संयोजक राजेश तिवाडी, सह संयोजक ओमप्रकाश शर्मा, महिला कार्य प्रमुख श्वेता जैन, महिला कार्य सह प्रमुख रेणू जैन तथा स्वावलंबी भारत अभियान नगर सह संयोजक का दायित्व संस्कार भारतीय को सौंपा।

कार्यशाला के मुख्य वक्ता स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक सतीश कुमार ने कहा कि हमें भारत को स्वावलंबी बनाकर युवाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार करना है। उन्होंने कहा कि लोगों को पढ़ाई– लिखाई के बाद नौकरी की तलाश होती है। सरकारी नौकरी की तलाश करने की बजाय हमें उन्हें रोजगार देने वाला बनाना चाहिए। भारत की बेरोजगारी, स्वरोजगार से ही दूर हो सकती है। कार्यशाला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक बाबूलाल ने कहा कि सोलहवीं सदी में भारत की जीडीपी 22 प्रतिशत थी, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद भारत की जीडीपी 3 प्रतिशत रह गई। इतिहास के दस्तावेजों में पता चलता है कि भारत की जीडीपी जब 22 प्रतिशत थी, उस समय इंग्लैंड की जीडीपी मात्र 3 प्रतिशत थी।

उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें स्वावलम्बी भारत बनाने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। कार्यशाला को स्वावलंबी भारत अभियान की अखिल भारतीय सह समन्वयक अर्चना मीना, स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत संयोजक देवेंद्र भारद्वाज, प्रांत संपर्क प्रमुख पं. राधेश्याम शर्मा ने भी संबोधित किया। कार्यशाला में विभाग संयोजक भगवान सहाय शर्मा, जिला संयोजक मनोज राघव, सह संयोजक महेश पालीवाल व राम सिंह नाथावत, विचार प्रमुख श्याम बिहारी शर्मा, महिला कार्य प्रमुख केसन्ती मीना, ललित शर्मा, राजेश तिवाडी, रेनू जैन, ईशा कुमारी, संस्कार भारतीय, ममता शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ❑❑

*https://www.bhaskar.com/local/rajasthan/dausa/news/workshop-of-swadeshi-jagran-manchs-prant-vichar-varg-and-self-reliant-india-campaign-131260820.html*

स्वदेशी गतिविधियां **स्वावलंबी भारत अभियान**

# प्रांतीय कार्यशालाएं व विचार वर्ग

सचित्र झलक

**मेरठ प्रांत**

**मध्य भारत प्रांत**

**उत्तर असम प्रांत**

**महाकौशल प्रांत**

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 मई 2023
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2021-23
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां **स्वावलंबी भारत अभियान**

# प्रांतीय कार्यशालाएं व विचार वर्ग

सचित्र झलक

**जयपुर प्रांत**

**विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश**

**मालवा प्रांत**

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती